वर्ष 1 अंक 5 मई 1979 एक रुपया

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू सम्मेलन विशेषांक

देश के कोयला मजदूरों की 18 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल

30 मई को श्रमिक महिला मांग दिवस मनाओ

सीटू का मई दिवस घोषणापत्र-1979

मई दिवस मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता का दिवस है. इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर हम समाजवादी देशों के मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए गर्मजोशी के साथ बिरादराना सलाम देते हैं. हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उस बहादुर जनता को भी सलाम करते हैं जो राष्ट्रीय मुक्ति के समर्थन और रंगभेद तथा साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध अपना दिलेराना संघर्ष चला रही है. इसके साथ ही हम उन विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को भी सलाम करते हैं जो आर्थिक संकट के बोझ के विरुद्ध और अपने जीवन-स्तर की रक्षा करने के लिए बहादुरी के साथ लड़ रहा है.

सीटू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फैडरेशनों का भी बिरादराना अभिनंदन करती है जिन्होंने मजदूरों मे एके की बढ़ती हुई भावना में अपना योग दिया है, पिछले दिनों एकता और साझी कार्रवाइयों में बढ़ोतरी हुई है. सीटू इसका स्वागत करती है. औद्योगिक संबंध बिल के विरुद्ध जो शानदार एकता सामने आयी वह आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सीटू पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है कि सभी संगठन, फैडरेशन और यूनियनें मिल कर संयुक्त कार्रवाइयां करने की कोशिशें जारी रखेंगे.

सीटू अपने जुझारू किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, नौजवानों और महिलाओं को भी सलाम करती है जो लगातार हमलों के खिलाफ संघर्ष का झंडा बुलंद किये रहे हैं.

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकारों ने अपनी जनसमर्थक नीतियों पर चलते हुए मजदूर वर्ग, किसानों और मेहनतकश जनता के लिए जो भारी काम किया है उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं.

साथियों, एमरजैंसी के बाद के हमारे अनुभव बताते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा और सामाजिक अन्याय जैसी जनता की बुनियादी समस्याएं तब तक दूर नहीं की जा सकतीं जब तक भा रत में मौजूदा आर्थिक ढांचा कायम है. हमारे देश में समाजवाद की स्थापना से ही इन बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सकता हैं. हमें खेत मजदूरों और किसानों के हितों के लिए डट कर काम करना होगा, और मूलगामी भूमि सुधारों तथा फालतू जमीन के बंटवारे की मांग करते हुए मजदूर-किसान एकता को मजबूत बनाने के लिए जी-जान से काम करना पड़ेगा. साथियों, एमरजैंसी का जुआ उतार फेंकने के बाद दो साल का वक्त बीत चुका है. लेकिन लोकतंत्र के लिए तानाशाही की उन्हीं ताकतों का आज भी खतरा बना हुआ है. देखते हैं कि संजय गांधी दुबारा से मैदान में आ रहा है. साथियों, एमरजैंसी के दौरान लोकतंत्र का दमन किया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया और प्रेस का गला दाब दिया गया. हमें अपना बोनस गंवाना पड़ा और उसके साथ ही हमारा विरोध और आंदोलन करने का अधिकार भी. हम किसी भी कीमत पर उस हालत को दुबारा नहीं पैदा होने दे सकते. हम कभी भी तानाशाही की ताकतों को दुबारा सत्ता में नहीं आने दे सकते.

आज भी मजदूर वर्ग की जीवन परिस्थितियों पर लगातार हमलें हो रहे हैं. जीवन-यापन के मूल्य सूचकांक में घांघली, बढ़ती कीमतों और वेतन जाम का आज भी उसे मुकाबला करना पड़ रहा है. बेरोजगारी, ले आफ, छंटनी, मिलबंदी. बरखास्तगी और विक्टिमाइजेशन में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है. एक तरफ इजारेदारों की दौलत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मजदूर वर्ग और आम जनता की गरीबी बढ़ रही है.

जनता सरकार की नीतियां इन तानाशाही की ताकतों को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर रही हैं. जनता सरकार ने अपने चुनाव के वायदों को तोड़ा है. उसने न सिर्फ मेहनतकश जनता को कोई माली राहत नहीं पहुंचायी है बल्कि उस पर टैक्सों का भारी बोझ भी लाद दिया है. इजारेदार और निहित स्वार्थ जनता पार्टी की हुकूमत से भी उसी तरह समर्थन और संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिस तरह वे कांग्रेस हुकूमत से करते थे. मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर यह सरकार भी हमला कर रही हैं. मिनीमीसा लगा दिया गया है. निवारक नजरबदी फिर से लागू कर दी गयी है. हालांकि हम संपत्ति के अधिकार को खत्म करने का स्वागत करते हैं लेकिन इस बात पर भी गौर करते हैं कि एमरजैंसी के तानाशाही निजाम के दौरान किये गये संविधान-संशोधनों से जनता के जो अधिकार छीने गये थे उन्हें पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है. यह मान लेने के बाद भी कि बोनस स्थगित वेतन है, बोनस भुगतान एक्ट में संशोधन करते हुए रेल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थाओं और दूसरे कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस दिलाने की व्यवस्था नहीं की गयी है. जनता सरकार भूतलिंगम पैनल की सिफारिशों की आड़ में वेतन जाम कर रही है और सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरो के आदेशों में उसके इरादों की अमली शक्ल देखी जा सकती है. ये सारी बातें ऐसी हैं जो तानाशाही की ताकतों को सारी स्थिति गड़बड़ाने और अपने हितों के लिए जनता के असंतोष का फायदा उठाने का मौका देती है.

ये सारी बातें ज्यादा मजबूत और अधिक संकल्पशील एकता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं. क्योंकि तभी तानाशाही ताकतों की प्रगति को रोका जा सकता है, मालिकों के हमलों से मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सकती है, और जनता सरकार के मजदूरविरोधी तथा जनविरोधी कदमों को हराया जा सकेगा. सीटू इस तरह की एकता कायम करने का संकल्प कर चुकी है. इस लिए वह सभी ट्रेड यूनियन संगठनों का आह्वान करती है कि निम्नलिखित मांगों का समर्थन करें :

1. **तानाशाही ताकतों को रोकना और लोकतंत्र की रक्षा.**
2. **देहातों और शहरों के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार**

[शेष पृष्ठ 35 पर]

जनता सरकार : आम आदमी को राहत नहीं

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे के माद्रास में 11 से 15 अप्रैल को हुए सीटू के चौथे सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के कुछ अंश

सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने मई 1975 में बंबई में हुए सी. आई. टी. यू. के तीसरे सम्मेलन के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय ख्याति के नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया. कामरेड रणदिवे ने इन नेताओं और ट्रेड यूनियन व मजदूर वर्ग आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

वियतनाम : सी. आई. टी. यू. की ओर से कामरेड रणदिवे ने वियतनामी जनता, जिस पर चीन की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया है, के साथ एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने वियतनाम पर चीनी आक्रमण की और उसे साम्राज्यवादी देशों से मिल रहे समर्थन की निंदा की.

बधाई : उन्होंने इंगलैंड, फ्रांस, इटली, और अन्य पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को उनके संघर्ष के लिए बधाई दी. उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों और उनकी जनता को हार्दिक बधाई दी "जो अभी कुछ ही वर्ष पहले मुक्त हुए हैं और श्वेत साम्राज्यवादी अल्पमत के जाति भेदी प्रभुत्व के खिलाफ कुछ हिस्सों में मुक्ति संघर्ष चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए लड़ रहेहैं."

अमरीकी षड़यंत्र : "पूंजीवादी दुनिया में गहरे जमे हुए आर्थिक संकट और अल्पविकसित दुनिया के पिछड़े हालात के बीच उन्नत साम्राज्यवादी देश एक परमाणु युद्ध की तैयारी में हथियारों का ढेर लगाते चले जा रहे हैं." इसकी ओर संकेत करते हुए कामरेड रणदिवे ने चेतावनी दी कि "अमरीकी साम्राज्यवाद बड़ी सक्रियता से सैनिक तैयारियों और नव-उपनिवेशवादी षड़यंत्रों में लगा हुआ है और वह समाजवादी खेमे की फूट का, सोवियत-चीनी मतभेदों का भरपूर फायदा उठा रहा है." अमरीकी साम्राज्यवाद की निर्लज्जतापूर्वक दखलंदाजी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि "भारत में यह सरकार पर परमाणु विस्फोट न करने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए और परमाणवि विकास में अपनी कठपुतली बनाने के लिए यह जोर डाल रहा है." लेकिन "इसकी सभी चालें कारगर नहीं हो रही हैं." ईरान, अफगानिस्तान व अन्य देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर हावी होने के इसके प्रयत्नों का हर जगह विरोध हो रहा है." उन्होंने "कम्पूचिया की नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना का समर्थन" किया.

सैनिक तानाशाही : "पाकिस्तान और बंगलादेश की जनता के साथ, अपनी गहरी एकजुटता और सहानुभूति प्रकट करते" हुए जो इस समय "सैनिक तानाशाही में पिस रही हैं" कामरेड रणदिवे ने कहा कि "यह कोई आकस्मिक बात नहीं है कि इस उपमहाद्वीप के तीनों देश 1975 और 1977 के बीच किसी न किसी प्रकार की तानाशाही के अधीन रहे. जहां भारत में इमरजेंसी की तानाशाही उठा ली गई है वहां बाकी दोनों देश अभी तक इसी शासन के अधीन है··· तानाशाही शासन लाने के लिए इन तीनों देशों में गहरी आर्थिक शक्तियां काम कर रही हैं. इन देशों की पूंजीपति जमीदार वर्गों की सरकार संसदीय सरकार को लंबे अरसे तक बनाए रखने के लिए असमर्थ हैं, खास तौर से उस समय जब अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही हो."

अभिन्न अग : लोकतंत्र की रक्षा के बारे में चर्चा करते हुए कामरेड बी. टी. रणदिवे ने कहा कि "तानाशाही को केवल तभी गुंजायश मिलती हैं जब वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतें या तो बहुत कमजोर होती हैं या उनमें फूट रहती है. प्राधिकारवादी ताकतों के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ना लोकतंत्र और समाजवाद के लिए संघर्ष का जीवंत और अभिन्न अंग है."

गुलामी : इमरजेंसी ने मजदूर वर्ग और आम जनता के सामने यह जाहिर कर दिया कि आम आदमी के अधिकारों के दमन के लिए तानाशाही किस हद तक जा सकती है. इसका जिक्र करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि "इमरजेंसी का मतलब था लोकतांत्रिक अधिकारों का खात्मा और पूंजीपति मालिकों के हाथों आर्थिक गुलामी." लेकिन "सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ कि मजदूर वर्ग इमरजेंसी को रोक नहीं सका, क्यों यह इमरजेंसी के शासकों के खिलाफ लगातार लड़ाई नहीं लड़ सका ?" इन सवालों का खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि "इसका कारण यह है कि मजदूर वर्ग अपनी आर्थिक लडाई में बहुत अधिक डूबा हुआ था, क्योंकि यह राजनीतिक फूट के कारण एकजुट नहीं हो सका, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक शक्तिशाली हिस्सा सिर्फ आर्थिक सहूलियतें पाने से ही पूरी तरह बंधा हुआ था और जनता पर क्या बीतती है इसकी परवाह किए बिना शासक पार्टी के साथ हो गया था."

हिमायत : इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि "तरह-तरह के सुधारवादी और संशोधनवादी जनता को बहकाते रहे कि इमरजेंसी का निशाना प्रतिक्रियावादियों को बनाया गया है न कि जनता को. ये ही लोग हैं जो कांग्रेस सरकार से सहयोग करके इसके तानाशाही शासन की हिमायत करते रहे. मजदूर वर्ग को सिर्फ

[शेष पृष्ठ 4 पर]

काम का अधिकार संविधान के तहत मूल अधिकार बनाया जाए

[पृष्ठ 3 से आगे]

अपनी एकता ही कायम नहीं करनी होगी बल्कि उसे किसी समझौतावादी विचार-धारा का शिकार होने से भी इंकार कर देना होगा. ऐतिहासिक अनुभव यह सिद्ध करता है कि तानाशाही और फासिज्म की नौबत आने पर कोई देश या राष्ट्र तभी उस खतरे को विफल बना पाता है जबकि मजदूर वर्ग संगठित रूप में इसका प्रतिरोध करता है और दूसरे वर्गों को इस लड़ाई में शामिल कर पाता है. भारत की आज की स्थिति में जब इंदिरा के नेतृत्व वाली शक्तियां फिर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है मजदूर वर्ग को अपनी पिछली गल-तियों से सीखे गए सबक याद रखना होगा और इस तानाशाही पार्टी के मसूबों का संगठित हो कर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा."

अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कामरेड रणदिवे ने कहा कि आज यह "ठहराव और आर्थिक संकट से निरंतर ग्रस्त है. इसके शिकार प्रमुख रूप से ग्राम किसान और खेतीहर मजदूर हैं, संगठित और असंगठित उद्योगों के औद्योगिक मजदूर और कर्मचारी हैं."

भारी कमी : विभिन्न आंकड़ों व सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष कामरेड रणदिवे ने कहा कि "इन दस वर्षों की अवधि में देहाती मजदूरों की चाहे वह खेतिहर मजदूर हों या गैर खेतिहर, मज-दूरी में बहुत बड़ी कमी हुई है और वे गरीबी के सीमांत बिंदु पर पहुंचा दिए गए हैं जबकि साथ ही उनके काम के अवसर भी कम हो गए हैं."

अहसास : देहाती इलाकों में हरित क्रांति के आगे बढ़ने के साथ-साथ आयों में बढ़ती असमानता की ओर इशारा करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि "ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर वर्ग को इस तथ्य का अहसास नहीं है कि उनके जीवन स्तर पर हो रहे हमलों के खिलाफ लड़ाई तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक वे ग्रामीण इलाकों में विषमताओं के खिलाफ मोर्चा नहीं लेते."

बोझ : उद्योग के क्षेत्र में ठहराव अब जीर्ण रूप ले चुका है और इसे पूंजीवादी विकास के तरीके से पैदा होने वाले आर्थिक संकट का अभिन्न अंग माना जा सकता है. इसके कारण मजदूर वर्ग पर हो रहे हमलों के खिलाफ ट्रेड यूनियन आंदोलन के नतीजों के बारे में कामरेड रणदिवे ने कहा कि "यद्यपि मजदूरों का वेतन पैसों में बढ़ता चला गया है पर उसकी वास्तविक मजदूरी में शायद ही कोई बढ़त हुई हो. अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग ने अपने जीवन स्तर पर होने वाले हमलों का बहुत बहादुरी से मोर्चा लिया है मगर फिर भी उसे इस संकट का बोझ ढोना ही पड़ रहा है."

गुंजायश : 1978-83 की योजना के मसौदे में दिए गरीबी की सीमा के नीचे बसर कर रहे लोगों की संख्या के अनुमान को नोट करते हुए कामरेड रणदिवे ने बताया, "इन्हीं वर्षों के दौरान सम्पति और साधन स्रोतों का भारी जमाव मुट्ठीं भर इजारेदारों के हाथों में हुआ." उन्होंने पूछा, "एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो संकट ग्रस्त हो, जिनमें देहातों की आम जनता जमींदारों, पूंजीपतियों और विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की अपार लूट के कारण क्रय शक्ति खो चुकी हों जिसमें स्वामित्व के संबंधों में पूरा बदलाव लाए बिना मजदूरों की अपनी जीवन दशा में आमूल सुधार लाने की क्या गुंजायश रह जाती है ?" फिर उन्होंने कहा, "पूंजीपतियों के एकाधिकार को खत्म करने और जमीन का खेत जोतने वालों में बटवारा करने के लिए संघर्ष छेड़े बिना उद्योग और उद्योगों में रोजगार की बढ़त के लिए गुंजायश नहीं है. विदेशी पूंजी के शोषण को पूरी तरह खत्म और सभी भारतीय इजारेदार संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किए बगैर हमारे पास उद्योगों में बेरोजगारी और मजदूरों तथा भारतीय जनता की गरीबी को खत्म करने का कोई आधार नहीं है."

अलगाव : देश में बढ़ती हुई बेरोज-गारी पर चर्चा करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "देहातों और शहरों दोनों ही में बेरोजगारी की समस्या आर्थिक स्थिति का केंद्रीय बिन्दु बनती जा रही है. यह बेतहाशा बाढ़ जिसके थमने का कोई आसार नहीं दिखाई देता, विकास के पूंजीवादी रास्ते का अनिवार्य परिणाम है जिस पर शासक वर्ग अग्रसर है···पूंजीवादी रास्ते पर उद्योगों के विकास में जितने लोगों को खपाया जाता है उनसे अधिक लोगों को हटाया जाता है और उसमें उत्पादक को उत्पादन के साधनों से अलगाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है."

काम का अधिकार : प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री डा. अमर्त्यसेन के अनुसार बेरोजगारों की संख्या 1971 में 4.24 करोड़ थी. यह आज की असलियत के काफी करीब है. यह पूछते हुए कि "इन परिस्थितियों में देहाती या शहरी इलाकों से आए हुए किसी नए मजदूर के लिए काम पाने की क्या गुंजायश रह जाती है" कामरेड रणदिवे ने कहा, "हर मजदूर को यह याद रखना होगा कि उसके बच्चों और रिस्ते नाते के बच्चों में से सौ के बीच सिर्फ तेरह को ही संगठित क्षेत्र में काम मिल सकता है और इनमें से सिर्फ चार-पांच को फैक्ट्री में काम मिल सकता है. इसी वजह से ट्रेड यूनि-यन आंदोलन को संगठित होकर इस बात की मांग करनी चाहिए कि काम के अधिकार को संविधान के अन्तर्गत एक बुनियादी अधिकार बनाया जाय."

नया खतरा : इस बारे में सी. आइ. टी. यू. के अध्यक्ष कामरेड रणदिवे ने कहा, "हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन की यह एक कमजोरी रही है कि इसने बे-रोजगारों की समस्या को नहीं उठाया और इसे अपने संघर्ष का एक अनिवार्य अंग नहीं बनाया···अब एक नया खतरा भी पैदा हो गया है. पूंजीपति निहित

[शेष पृष्ठ 5 पर]

हड़तालियों के विरुद्ध बेरोजगारों के नाम पर हिंसा शुरू

[पृष्ठ 4 से आगे]

स्वार्थों के लोग और उसके गुर्गे यह नारा देकर कि अधिक वेतन नहीं बल्कि अधिक नौकरियों की जरूरत है, बेरोजगारों और रोजगार वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. रोजगार शुदा मजदूरों को अधिक तंखाह पाने की मांग के सामने अधिक नौकरियां तैयार करने का सवाल बेरोजगारों को बहकाने के लिए उठाया जा रहा है."

विरोध : उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि "हड़तालियों के विरुद्ध बेरोजगारों के नाम पर हिंसा शुरू हो चुकी है." "यह एक चेतावनी है" जिसके प्रति सतर्क रहना जरूरी है. जनता सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की पेचीदा नीतियों को अभी तक नहीं छोड़ा है. इस पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आंचलिक और प्रांतीय भावनाएं उभार कर शासक वर्ग यह दिखाना चाहते हैं कि किसी राज्य की बेरोजगारी की समस्या को तभी हल किया जा सकता है जबकि दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य की सीमाओं से बाहर काम की तलाश करने से रोका जा सके और ये ही लोग हैं जो राष्ट्रीय एकता की, भारत की अखंडता की और भारत माता का शोर सबसे ऊंची आवाज में मचाते हैं और जनता पर इस नाम पर कि वह पूरी तरह एक है, एक भाषा लादना चाहते हैं."

जाति भेद : कामरेड बी. टी. रणदिवे ने यह बताते हुए कि "बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष में सिर्फ आंचलिक नजरियों के कारण ही रुकावट नहीं आती है बल्कि इसमें जाति भेद के कारण भी बाधा पड़ती है," कहा, "चूंकि सरकार और अधिकारी खरे ढंग से बेरोजगारी समस्या को हल करने में नाकाम हैं इसलिए वे शोषित जातियों और उपजातियों के लिए कामों और पदों के आरक्षण देते हैं और यह भ्रम खड़ा करते हैं कि यह उनकी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल कर देगा. इस प्रकार के संरक्षण का मकसद है बेहद दबे हुए लोगों को गुमराह करना और उन्हें पूंजीवादी जमींदार सरकार की नीतियों से मजबूती से बांध रखना. भारतीय परिस्थितियों में नितांत दबे हुए लोगों के लिए कुछ खास सहूलियतों का पूरी तरह विरोध करना तो गलत होगा पर साथ ही मजदूर यूनियनों को इसमें दखल देना होगा और सभी तबकों को बताना होगा कि वे बेरोजगारी और गरीबी की विकरालता के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक संगठित होकर खड़े हों."

समर्थन : लघु उद्योग के सिलसिले में कामरेड रणदिवे ने कहा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को छोटे उद्योगों को सुरक्षित रखने के सभी सच्चे उपायों का समर्थन करना चाहिए."

राष्ट्रीयकरण : जनता पार्टी के कुछ नेता जब तक इजारेदारों के स्वामित्व में आने वाले कुछ बड़े संस्थापनों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं. इसकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, "यह कुछ खास मतलब से एक दबाव डालने की तरकीब मालूम होती है न कि राष्ट्रीयकरण की सच्ची चिंता." राष्ट्रीयकरण के प्रति अपने नजरिए को स्पस्ट रूप से पेश करते हुए उन्होंने कहा, "सी. आई. टी. यू. सभी इजारेदार प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण के हक में है और जनता सरकार इस दिशा में जो भी सच्चे प्रयत्न करेगी उनका यह समर्थन करेगी. मगर साथ ही यह इस बात की भी मांग करती है कि राष्ट्रीयकरण का नतीजा नौकरशाही नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिष्ठानों के प्रबंध में मजदूरों की सच्ची साझेदारी होनी चाहिए. और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ इन प्रतिष्ठानों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपना या उनके हाथ बेचना नहीं होना चाहिए जैसा कि 'भेल' में प्रबंधकों की ओर से जोरदार विरोध और उद्योगमंत्री के खेद प्रकाशन के बावजूद होता दिखाई दे रहा है."

राहत : पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार को राज्य में औद्योगिक मजदूरों के लिए बेरोजगारी से राहत की एक प्रणाली शुरू करने के लिए बधाई देते हुए कामरेड रणदिवे ने बताया कि "महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी ही एक योजना तैयार की है और हैरत इस बात की है कि केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देने के लिए सलाह देने में काफी लम्बा समय लगाया."

झूठे दावे : जनता सरकार के कीमतों में गिरावट और कीमतों को नियंत्रित करने में अपनी सफलता के दावों को झूठा बताते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा "असलियत यह है कि जनता शासन में न केवल कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि कीमतें उससे भी ऊंचाई पर है जहां वे इमरजेंसी के पहले के मुद्रा प्रसार के दौर में थी." उन्होंने कहा, "क्योंकि जनता सरकार ने भी कांग्रेस सरकार के रास्ते पर ही घाटे की वित्त व्यवस्था का बदनाम तरीका ही अपनाया है" इसलिए कीमतों की घटाए जाने में जनता सरकार "पूरी तरह से नाकामयाब हुई है."

चुप्पी : हड़तालों और तालाबंदियों का जिक्र करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "पूंजीपतियों के प्रवक्ता हड़तालों का विरोध करने और इस बात का प्रचार करने में एक दूसरे से बाजी मार लेना चाहते हैं कि उत्पादन का कितना नुकसान होता है, मगर वे तालाबंदियों से जानबूझ कर पैदा किए गए उत्पादन नुकसान पर चुप साधे रहते है." तालाबंदियां अधिक लंबे समय तक चलती हैं. इनसे होने वाला नुकसान हड़तालों से होने वाले नुकसान से कई गुना ज्यादा होता है. इसके आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा, "यदि यह सरकार तालाबंदियों की कठोरता को मान ले और उसे समाज विरोधी और राष्ट्रीय उत्पादन में रुकावट डालने वाला कहकर उसकी

[शेष पृष्ठ 6 पर]

ट्रेड यूनियनों की मान्यता का फैसला गुप्त मतदान से हो

[पृष्ठ 5 से आगे]

निंदा करे तो भला यह एक वर्ग सरकार कैसे रह जाएगी."

कर : जनता पार्टी के शासन से आम आदमी को कर की राहत नहीं मिली है. इसकी विवेचना करते हुए सी. आई. टी. यू. अध्यक्ष ने कहा, "जनता सरकार के पिछले बजट में भी आम आदमी पर कर बढ़ाया गया था, जबकि इसमें बड़े व्यापारियों को कुछ राहतें दी थी: 1979-80 के बजट में बोझों को और बढ़ाया ही गया है." इस कराधान के भयानक चरित्र का सार कार्ल मार्क्स के शब्दों में देते हुए कहा, "आधुनिक वित्त-तंत्र की धुरी है जीवन निर्वाह के सबसे आवश्यक साधनों पर कर लगाकर (और इस तरह उनकी कीमतें बढ़ा देना) इसके भीतर ही एक स्वचालित शृंखला है. अधिक कर एक घटना नहीं बल्कि एक सिद्धांत है. वेतन भोगी वाले श्रमिक की हालत पर इसका जो विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उसकी यहां हम चिंता छोड़ भी दें तो किसानों, कारीगरों और एक शब्द में कहें तो निम्न मध्यवर्ग के सभी तबकों से जबरदस्ती लूट-खसोट की जाती है."

राजनीतिक खतरा : जनता पार्टी नए जोश-खरोश के साथ ऐसी नीतियों को अपना रही हैं जो देश की पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भरता को बढ़ाती हैं. इसकी आलोचना करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं पर अधिकाधिक निर्भर होती जाती है···इससे निजी पूंजी को अधिक आजादी मिल गई है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां रियायतों के लिए बड़ी-बड़ी मांगें करने लगी है··· निर्यात बढ़ाने और विदेशी बाजारों में कदम जमाने की बेतहासा कोशिश के कारण विदेशी इजारेदार फर्मों के साथ प्रतिष्ठान इस उम्मीद में कायम किए जा रहे हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में उप अनुबंध प्राप्त किए जा सकें. सहायता अनुदान प्राप्त निर्यात को बढ़ावा देने और स्वदेश में सहूलियत देने के लिए आयात में ढील और विदेशों से इन्हें जुटाने की समूची नीति के कारण भारत में और बाहर विदेशी पूंजी के साथ साझेदारी की कोशिश की जा रही है. इनमें जो राजनीतिक खतरे बने हुए हैं उन्हें आसानी से देखा जा सकता है."

दमन : संगठित मजदूर वर्ग पर ढ़ाए जा रहे दमन की ओर ध्यान दिलाते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि औद्योगिक संबंध विधेयक, जिसे मजदूर वर्ग ने नामजूर कर दिया है, के साथ "एक और बिल में अध्यापकों, नर्सों आदि की हड़तालों पर रोक लगाने का इंदिरा सरकार ने जो कुछ किया उससे भी आगे बढ़ जाने का प्रस्ताव रखा गया है."

हमले : सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों की मांगों का विरोध किया जा रहा है. ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज समझौता वार्ताओं में दखलंदाजी करता है. इसकी चर्चा करते हुए कामरेड रणदिवे ने यह भी बताया कि मजदूर वर्ग पर मालिकों के भाड़े के गुंड़े लगातार हमले करते हैं. इनमें पुलिस की भी सांठगांठ रहती है. अनेक जगहों पर ये मालिकों की स्थाई सेना बने हुए हैं इन्हें अक्सर चौकसी विभाग का आदमी कहा जाता है और हथियार रखने का लाइसेंस मिला होता है जिनका वे इस्तेमाल मजदूरों के खिलाफ करते हैं." मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अपने साथियों को जो बहुत बड़ी कुर्बानी देकर और असाधारण साहस दिखाते हुए सीटू के झंडे को लेकर चल रहे हैं बधाई देते हुए आह्वान किया कि "सीटू तथा दूसरे ट्रेड यूनियन आंदोलनों को मालिकों द्वारा रखे गए इन गिरोहों के हथियार वापस लिए जाने की मांग करनी चाहिए."

तमिलनाडु : कामरेड रणदिवे ने तमिलनाडु सरकार की "तमिलनाडु बंद के दौरान कठोर दमन" करने और "अपने एजेंटों को मजदूरों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल" करने के लिए आलोचना की. और उन्होंने कहा, "तभी से इसने हड़ताल विरोधी रवैया अपना रखा है और जहां मजदूरों के खिलाफ यह ताकत का इस्तेमाल करती रही है वहीं ऐसे मालिकों के प्रति जो इसकी हिदायतों की कोई परवाह नहीं करते है उनके प्रति खुशामंदी से काम लेती रही है."

उधार : ट्रेड यूनियनों की होड़ और सरकार के रवैये की चर्चा करते हुए कामरेड रणदिवे न कहा कि, "जनता श्रम मत्री और उनके मंत्रालय ने कांग्रेसी बारूदखाने से मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बदनाम करने के सारे हथियार उधार ले रखे हैं, जब कभी मजदूर संघर्ष में जुटे होते हैं और सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं तो श्रम मंत्री भी कहते हैं कि यह सब ट्रेड यूनियनों की होड़ और बहुत सी ट्रेड यूनियनों के होने के कारण है."

स्पष्ट : उन्होंने आगे कहा "कांग्रेस सरकार इस तरह का आरोप तब लगाती थी जब ट्रेड यूनियनों में तात्कालिक मसलों पर तीखा मतभेद हुआ करता था. मगर श्रम मंत्री ये आरोप उस समय लगा रहे हैं जब ट्रेड यूनियन केंद्र सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अधिकाधिक एकजुट हो रहे हैं. औद्योगिक संबंध विधेयक के विरोध में हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन ने श्रम मंत्री को छोड़कर हर आदमी को इस आंदोलन की बढ़ती हुई एकता को स्पष्ट कर दिया."

विश्वासनीयता : कामरेड रणदिवे ने इस सचाई को नोट किया कि "यूनियनें बहुत है. अनेक सवालों पर इन यूनियनों के अलग-अलग रुख हैं." उन्होंने बताया, "यूनियनों की भरमार इसलिए हुई कि अधिकांश मालिकों और सरकार ने सामूहिक सौदेबाजी के लिए अपनी पालतू यूनियनों को ही मान्यता दी. इन मान्यता प्राप्त यूनियनों ने मजदूरों के पीठ पीछे समझौते कर लिए और अपनी विश्वसनीयता खो दी."

[शेष पृष्ठ 18 पर]

एकता व एकजुट संघर्ष का झंडा बुलंद करो

सीटू महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति द्वारा मद्रास में 11 से 15 अप्रैल को हुए सीटू के चौथे सम्मेलन में पेश की गई जनरल रिपोर्ट के कुछ अंश

सी. आई. टी. यू. के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति ने अपनी जनरल रिपोर्ट में मौजूदा दौर में मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच पैदा हुई उत्साहवर्द्धक एकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए आशा व्यक्त की कि आने वाले दौर में एकता और संयुक्त कार्यवाहियों की जबरदस्त संभावनाएं हैं.

स्वाभाविक : मई 1975 के तीसरे सीटू सम्मेलन के तुरंत बाद घटित कुछ अभूतपूर्व घटनाओं की वजह से यह चौथा सम्मेलन दो साल की देरी के बाद हुआ है. इस घटनाक्रम का खुलासा पेश करते हुए कामरेड राममूर्ति ने बताया कि "हमारा संगठन इमरजेंसी का भयंकर शिकार हुआ. ऐसा होना स्वाभाविक ही था. इमरजेंसी से पहले के दिनों में सीटू ने ही मजदूर वर्ग को, ठोस और महत्वपूर्ण मामलों को लेकर, लामबन्द करने में सरकार और मालिकों के हमलों का प्रतिरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. इमरजेंसी का उद्देश्य शोषक शासक वर्गों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ते हुए जनवादी व्यापक प्रतिरोध को रोकना था. अतः स्वाभाविक तौर पर सीटू उनके हमले का मुख्य निशाना बनी."

सराहना : हमारे हजारों काडर व कार्यकर्त्ता, केंद्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल काउंसिल, राज्य व जिला कमेटियों के सदस्य बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिए गए थे. कुछ राज्यों में, जैसे कि राजस्थान में, वर्क्स कमेटी के चुने हुए सदस्यों तक को जेलों में इस लिए डाल दिया गया था क्योंकि वे सीटू के थे. कामरेड राममूर्ति ने सराहना करते हुए कहा कि "इस बात का श्रेय उनको देना ही होगा जो उस हमले से बिचलित नहीं हुए."

लामबंद : मजदूर वर्ग को समूची जनता की आजादी व अधिकारों पर होने वाले भयंकर हमले के खिलाफ गंभीर राजनीतिक कार्यवाही के लिए लामबंद नहीं किया जा सका. इसकी वजह बताते हुए कामरेड पी. राममूर्ति ने कहा कि "समूचा ट्रेड यूनियन आंदोलन बंटा हुआ था, और यह सच्चाई भी थी कि एटक और इंटक के नेताओं ने इमरजेंसी का पूरा समर्थन कर दिया था तथा उसे फासीवाद और प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई का दर्जा दे दिया था. मगर जल्दी ही, इमरजेंसी का सही मकसद एटक और इंटक से संबंध रखने वाले मजदूरों को भी मालूम हो गया था".

फर्क : पश्चिम बंगाल में 50,000 चटकल मजदूरों की इमरजेंसी में छटनी हुई. कुख्यात बोनस कानून द्वारा बोनस छीना गया. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का बोनस समझौता रद्द किया गया. लेकिन इंटक और एटक के नेता इंदिरा के 20 सूत्री कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन कर रहे थे. इसके विपरीत, कामरेड राममूर्ति ने बताया "कई राज्यों में हमारे सक्रिय साथी जो पकड़े जाने से बच गये थे, लुक छिपकर रह रहे थे और मजदूरों से संपर्क बनाए हुए थे. सारे अधिकारों के छिन जाने के बावजूद, कुछ महीनों बाद, इतनी कठिन हालतों में भी संघर्ष छेड़े गए थे" और इनके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा "सरकारी सूत्रों के अनुसार इमरजेंसी के दौरान 2,000 हड़ताली कार्यवाहियां हुई."

गुप्त बैठक : कामरेड राममूर्ति ने उस गुप्त बैठक का जिक्र किया जिसमें सीटू, एच. एम. पी., बी. एम. एस. और एच. एम. एस. का वह भाग जो इमरजेंसी के समर्थकों से अलग हुआ था, इन सबके प्रतिनिधि गुप्त रूप से एक जगह मिले थे और उन्होंने मिलकर एक बयान जारी किया था जिसमें मजदूरों से अपील की गई थी कि वे एकजुट होकर बोनस पर किए गए हमले का हर तरह से मुकाबला करें. लेकिन एटक ने एकजुट कार्यवाहियों में भाग लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

शानदार भूमिका : उन्होंने मार्च 1977 के चुनावों में मजदूर वर्ग की शानदार भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा "पूरे देश में ऐसे सभी संसदीय चुनाव क्षेत्रों में जहां मजदूर वर्ग ज्यादा तादाद में था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस और उनके सहयोगी बुरी तरह से हारे."

असली चेहरा : इमरजेंसी के बाद की स्थिति पर विचार करते हुए सीटू महासचिव ने जनता पार्टी के वायदों की समीक्षा करने के साथ उसके द्वारा ट्रेड यूनियन और जनतांत्रिक अधिकारों की बहाली, रेलवे मजदूरों के विक्टिमाइजेशन को समाप्त करना आदि अनेक ऐसी प्रारंभिक कार्यवाहियों को भी सामने रखा. "मगर" उन्होंने कहा, "जल्द ही सरकार की आर्थिक नीतियां आपने आप सामने आने लगीं जो कि किसी भी मायने में पिछले शासन से भिन्न नहीं हैं. बहुत से मंत्रियों और सरकारी हाकिमों ने उसी तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं जिन्हें पिछली सत्ता मजदूरों की मजदूरी संबंधी मांगों पर लगाया करती थी. यह सब जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए वायदों से बिल्कुल उलटा कदम था, इन्होंने भी आमदनी, मजदूरी व कीमतों की नीति के सिलसिले में खेतिहर मजदूरों को संगठित मजदूरों के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की."

अहम मसले : कामरेड राममूर्ति ने

[शेष पृष्ठ 8 पर]

सरकार का इरादा केवल वेतन जाम करना है

[पृष्ठ 7 से आगे]

सीटू की पहल पर सितंबर 1977 में दिल्ली में ट्रेड यूनियनों की अखिल भारतीय कांफ्रेंस के अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया उन्होंने बताया "इस सम्मेलन ने ऐसे दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो आज के मजदूर वर्ग को जनता के सामने अहम थे. पहला मसला था उस निरकुशतावादी ढांचे को मटियामेट करना जिसे 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा बनाया गया था और दूसरा मसला था मजदूरी, आमदनी और कीमत निर्धारण नीति का."

बहिष्कार : इस सम्मेलन के बाद, उक्त प्रस्ताव के तहत पूरे देशमें अनेक जगहों पर दूसरे संगठनों से मिलजुलकर मीटिंगें की गई. राज्य कमेटियों व अनेक ट्रेड यूनियनों ने सम्मेलन के प्रस्ताव को विभिन्न भाषाओं में छापा और व्यापक तौर पर मजदूरों के बीच बांटा. "इस सबके बावजूद, सरकार ने इस अहम मसले पर ट्रेड यूनियनों के केन्द्रों द्वारा की गई बात के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई," इसके बदले, उसने खेत मजदूरों की हालत सुधारने के नाम पर वेतन जाम करने की नीयत से "एक रिटायर आई. सी. एस., श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त कर दी." ट्रेड यूनियन आंदोलन ने, निजी स्वार्थों से भरी इस कमेटी की कार्यवाहियों का बाहिष्कार किया.

ब्यूरो : ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज (बी. पी. ई.) जिसे शुरू में सार्वजनिक उद्योगों के वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के लिए बनाया गया था अब एक ऐसा बड़ा संगठन हो गया है जो सार्वजनिक उद्योगों में मजदूरी संबंधी समझौतों को काबू में रखने का पुर्जा बन गया है. इसकी तीखी आलोचना करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "उसने सारे सार्वजनिक उद्यागों को एक हुक्म भेजा है जिसकी वजह से प्रबन्धकों ने किसी भी तरह के समझौते पर बातचीत करने से इन्कार कर दिया. यह एक तरह से सार्वजनिक उद्योगों के लिए सचमुच मजदूरी जाम करने वाला काम था. जाहिर है कि अगर यह नीति सफल हो जाने दी जाती, तो निजी क्षेत्र में भी मालिकान सरकार का उदाहरण लेकर मजदूरी जाम करने की हरकत शुरू कर देते."

सराहना : इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही के लिए कामरेड राममूर्ति ने विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों की सभी ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने की सीटू की लगातार कोशिशों की सराहना की. इसमें 1977 के अंत में हुई हैदराबाद कांफ्रेंस, 20 जनवरी 1978 को सार्वजनिक क्षेत्र में वेतनजाम के विरूद्ध विरोध दिवस मनाने का फैसला, तथा इसके विरोध में हुए अनेक प्रदर्शन और अन्य कार्यवाहियां विशेष उल्लेखनीय है.

चाल : सरकार और ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने मजदूरों को कार्यवाही से रोकने के लिए एक चालाकी भरी चाल खेली और एक आदेश जारी किया कि जहां जहां समझौतों की अवधि खत्म हो गई है वहां नए समझौतों पर बातचीत शुरू की जाए. उन्होंने बताया कि इससे "मजदूरों में यह भ्रम फैला दिया गया कि 20 जनवरी को किए गए उनके संघर्ष ने सरकार की नीति में तबदीली करवा दी. वे समझौते लंबे अरसे तक खिंचते गए और जल्द ही सारे भ्रम टूट गए."

निंदा : अधिकांश ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा मिलकर 15 मई, 1978 को दिल्ली में किया गया सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अब तक हुए मजदूर सम्मेलनों में सबसे सफल था. इसमें एक स्वर से ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की मनाही करने वाले आदेश की निंदा का प्रस्ताव पास हुआ और 10 जून 1978 को देश भर के सार्वजनिक उद्योगों में एक "अखिल भारतीय दिवस" और 28 जून 1978 को देश के सभी सार्वजनिक उद्योगों में एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया गया.

सुस्तकदमी : जब सारे सार्वजनिक उद्योगों में इस कार्यक्रम पर जोरशोर से तैयारियां चल रही थी तब सरकार ने घुटने टेक दिए और हड़ताल से कुछ दिन पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं से बात करने पर राजी हुई. कामरेड राममूर्ति ने बताया कि "सरकार की ओर से मीटिंग में श्रममंत्री, उद्योगमंत्री, तेल-रसायन मंत्री और वित्तमंत्री ने हिस्सा लिया. ...आखिर में यह तय हुआ कि निर्देशों को ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों के मशविरे से ही बनाया जायगा और इसके लिए समिति का गठन किया जायगा. यह भी तय किया गया कि ये निर्देश लचीले होंगे और उन्हें कठिन आदेश का पर्याय नहीं माना जायगा. इसके बाद यह भी तय हुआ कि जीवन बीमा निगम में बोनस के सवाल पर समझौते के लिए बात चीत शुरू होगी. उनका बोनस इकतरफा तरीके से प्रबंधकों ने छीन लिया था... इस समझौते को लागू करने में सरकार सुस्तकदमी से चली...केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक सामूहिक पत्र सरकार को लिखा जिसमें कहा गया कि अगर वायदे के मुताबिक बातचीत के लिए समिति का गठन तुरंत नहीं किया गया तो वे सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को सीधी कार्यवाही करने की सलाह देने को मजबूर होंगे." लेकिन सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो बातचीत को ठप्प करने वाले थे.

लक्ष्य : सीटू के महासचिव ने कहा कि "इन सब बातों से यह साफ जाहिर है कि इस सवाल पर चुनाव-वायदों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है....

[शेष पृष्ठ 9 पर]

संघर्षरत मजदूरों पर एक साल में 11 बार गोलियां चलाई गई

[पृष्ठ 8 से आगे]

जीवन यापन के मूल्यों में बढ़ोतरी को नामंजूर करने का यह मतलब है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ मजदूरी जाम करना ही नहीं है बल्कि असली मजदूरी में भी धीरे धीरे कटाव करना है. इस नीति को समूचे मजदूर वर्ग की सामूहिक ताकत द्वारा शिकस्त दी जानी चाहिए और सीटू को ऐसे सामूहिक संघर्षों के लिए कदम उठाने होंगे."

कामरेड राममूर्ति ने घृणित औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ मजदूर वर्ग द्वारा शुरू किए संघर्षों का विस्तार से हवाला दिया. ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में 19 नवम्बर, 1978 को हुआ सफल मजदूर सम्मेलन तथा 20 नवबंर 1978 को हुई विशाल रैली ने सरकार को परेशानी में डाल दिया और राज्यसभा के नवंबर-दिसंबर अधिवेशन में इस बिल को न रखने के लिए मजबूर होना पड़ा.

संघर्ष : और बहुत सारे मसलों को लेकर भी सामूहिक संघर्षों की शुरुआत हुई. कामरेड राममूर्ति ने बताया कि "हर राज्य में मजदूरी व बोनस के आर्थिक मसलों को लेकर तथा छंटनी के खिलाफ मजदूरों के सामूहिक संघर्ष पिछले दो वर्षों में इतने भारी पैमाने पर हुए हैं जैसे पहले कभी नहीं देखे गए थे. इनमें से पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों की हड़ताल सबसे बड़ी रही जिसमें डेढ़ लाख मजदूरों ने हिस्सेदारी की, आखिरकार मालिकों को झुकना पड़ा और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी रु० 62.10 की बढ़ोतरी मजदूरों को दी. पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग मजदूरों की हड़ताल की धमकी से प्रबंधकों को 65 रुपये की बढ़ोतरी के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे ही संघर्ष तामिलनाडु, केरल, राजस्थान, और अन्य जगहों में भी हुए. इसी सिलसिले में, सीटू ने जो दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों से मिलकर राजस्थान के अणु शक्ति कारखाने में लम्बी हड़ताल चलाई, वह काफी महत्वपूर्ण है."

तेजी : पिछले दो वर्षों में संघर्षों में और अधिक तेजी आई है. इसका जिक्र करते हुए कामरेड राममूर्ति ने बताया कि आज "औद्योगिक मजदूर ही नहीं, मध्यम वर्ग के कर्मचारी भी सामूहिक संघर्ष में उतर पड़े हैं." इस दौरान जो संघर्ष हुए उनमें कुछेक महत्वपूर्ण संघर्ष इस प्रकार है : महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की 73 दिन तक चली हड़ताल, बिहार राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबी हड़ताल, बिहार, आंध्र, केरल और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की लंबी हड़तालें जिन्हें आवश्यक सेवा कानून के तहत गैर कानूनी करार देकर भी तोड़ा नहीं जा सका, राजस्थान की खेतड़ी कापर खानों के मजदूरों की हड़ताल, मजदूरी बढ़ाई जाने और बी. पी. ई. की दखलंदाजी बंद कराने की मांग को लेकर 6 लाख कोयला खदान मजदूरों की 5 फरवरी 1979 की हड़ताल, दोनों फेडरेशनों से संबंधित बैंक कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल, वेतन समझौतों पर पुर्नविचार करने के लिए जीवन बीमा निगम की सभी यूनियनों द्वारा एक दिन की हड़ताल, वेतन बढ़ाने के लिए बंबई कपड़ा मिलों के डेढ़ लाख मजदूरों की एक दिन की हड़ताल जिसमें मान्यता प्राप्त इटंक की यूनियन को छोड़ कर सभी यूनियनों ने भाग लिया. सार्वजनिक उद्योग बालमेर लावरी में मजदूरों की दो माह लंबी हड़ताल, पुलिस दमन के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर सोनीपत और फरीदाबाद के संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की एक दिन की हड़तालें और आंदोलन जिनमें अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के अफसर भी ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ आए.

महत्वपूर्ण भूमिका : एकता बनाने और एकजुट होकर संघर्ष करने का काम बड़ा कठिन है और इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है. इस पर प्रकाश डालते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि सीटू ने "कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय हासिल की है और सामूहिक संघर्षों को कराने में अहम भूमिका अदा की है. इसकी वजह यह रही है कि सीटू ने ऐसे मसलों को उठाया जिनका ताल्लुक सभी मजदूरों और कर्मचारियों से था और मजदूरों के बीच लगातार जद्दोजहद को आगे बढ़ाया."

उज्ज्वल भविष्य : उन्होंने आशा व्यक्त की "आने वाले समय में एकता और एकजुट संघर्षों में पुरजोर तेजी आएगी. इसकी वजह यह है कि जनता सरकार जिन आर्थिक नीतियों पर चल रही है, वे किसी भी मायने में उनसे पहले वाली सरकार [यानी कांग्रेस सरकार] से भिन्न नहीं है. मजदूर-विरोधी नीतियों की जड़ सरकार की इन्ही बुनियादी आर्थिक नीतियों में छिपी है."

दमन : सीटू के महासचिव ने संघर्षरत मजदूरों पर ढाए जा रहे अत्याचारों और पुलिस दमन का विस्तार से हवाला दिया. उन्होंने बताया, कि उत्तर प्रदेश, में पंत नगर के हड़ताली मजदूरों पर, हरिद्वार के 'भेल' कारखाने और कानपुर के स्वदेशी कपड़ा मिल के मजदूरों पर सिर्फ इस वजह से गोलियां चलाई गई क्योंकि वे काफी महीनों से प्रबंधकों द्वारा अदा न की गई मजदूरी की मांग कर रहे थे. ऐसा ही और भी कई जगह हुआ. गाजियाबाद में, मजदूरों पर मालिकों के पालतू गुन्डों ने गोलियां बरसाई जबकि उन्होंने साइकिल स्टैंड, कैंटीन वगैरह की सुविधा की मामूली-सी मांगें की थी. हजारों बिजली कर्मचारी गिरफ्तार किए गए. इस तरह एक साल में ग्यारह जगह मजदूरों पर गोली कांड हुए हैं. फरीदाबाद में, हरियाणा सरकार ने उन मजदूरों को आतंकित करने के लिए पुलिस छोड़ दी जो सीटू के झंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे और मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए अभियान कर रहे थे." उन्होंने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में गोली कांडों और मजदूरों के ट्रेड यूनियन आंदोलन पर दमन की मिसालें दें.

[शेष पृष्ठ 10 पर]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली दावत

[पृष्ठ 9 से आगे]

रवैया : ज्यादातर सार्वजनिक उद्योग अपने बहुत से स्थायी मजदूरों को ठेकेदारों के हाथों सौंपती रही है. सरकार ने दो साल के बाद भी बोनस नीति नहीं बनाई है. सरकार ने अब तक वेतन-जाम की नीति की घोषणा कर दी होती मगर देशव्यापी हड़तालों का सामना करने की आशंका से वह ऐसा न करने के लिए मजबूर रही है. मगर उस दिशा में कोशिशें जारी हैं. रेलवे अपने मजदूरों को बोनस देने से इंकार कर रहा है. यह कितनी शर्मनाक बात है कि रेलवे के कुछ मजदूरों में से लगभग 20 प्रतिशत कैजुअल मजदूर हैं. इतना बड़ा हिस्सा तो अंग्रेजों के राज्य में भी कैजुअल मजदूरों के रूप में नहीं रखा जाता था. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की बोनस की मांग के प्रति भी भी सरकार का वही मजदूर विरोधी रवैया है. सरकार के इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "औद्योगिक संबंध विधेयक में तो मजदूर वर्ग विरोधी इन नीतियों की हद ही हो गई."

बजट : कामरेड राममूर्ति ने सरकार के बजट की आलोचना करते हुए कहा कि "1978-79 का बजट उन बुनियादी नीतियों से कतई अलग नहीं है जिनकी वजह से मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां अपनाई जाती रही हैं. दूसरी तरफ आम जनता पर नए बोझ डालने का इसमें पूर्वाभास मिलता है. 600 करोड़ रूपए से ऊपर के अब तक के सबसे भारी जो नए कर लगाए गए हैं और 1,300 करोड़ रुपए से ऊपर का जो अभूतपूर्व घाटा दर्शाया गया है उससे निश्चय ही कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी."

खुलीदावत : भारत सरकार की नीति का एक और जरूरी पहलू जो देश के आर्थिक विकास के लिए गम्भीर खतरा पैदा करता है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पूंजी विनियोग के लिए खुली दावत देना तथा उनसे समझौता करना है. इसकी ओर संकेत करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "इन विदेशी कम्पनियों से समझौता करने के लिए विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून में लगातार ढील दी जा रही है. ऐसा विश्व बैंक के इशारों पर किया जा रहा है जो चाहता है कि विदेशी पूंजी को भारतीय मंडी में खुली छुट दी जाय. सरकार के इस नरम रुख से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों की हिम्मत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और वे और भी अधिक छूट की मांग कर रहे हैं. भारत-अमरीकी व्यापार मंडल के संयुक्त अध्यक्ष श्री फ्रीमैन ने हाल में ही बड़ व्यापारिक घरानों व विदेशी पूंजी विनियोग के प्रति भारतीय उद्योग मन्त्री श्री फर्नांडीज के नरम-गरम विचारों की तीखी आलोचना की है. इसे नोट करते हुए उन्होंने कहा कि "श्री फ्रीमैन किसी भी एटलांटिक देश मे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे. लेकिन भारत की नीति की आलोचना करते हुए उन्होने मालिकों जैसा घमड दिखाया व मांग की कि बहुराष्ट्रीय विदेशी दवा कम्पनियों को भारत की मंडी तथा लोगों को लूटने की पूरी आजादी होनी चाहिये."

शर्म : अफसोस जाहिर करते हुए सीटू के महासचिव ने बताया कि "भारत-अमरीकी कांउसिल में भारतीय प्रतिनिधि सरकार को यह राय देने के लिए एकदम तैयार हो गए कि हालात का पुनर्मूल्यांकन किया जाए व 'फेरा' समझौते की शर्तों में ढील दी जाए. इन प्रतिनिधियों को भारत के दवा क्षेत्र के साथ दगा करने व अपनी अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र विकास को बलिदान करने में जरा भी शर्म न आई." इन प्रतिनिधियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये "विदेशी पूंजी के साथ मिलकर व्यापार करने, शिकमी ठेके लेने व एजेंसी में भागीदारी करने में दिलचस्पी रखते हैं."

दुमुंही नीति : भारत के उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीज जहां एक ओर कोका कोला कम्पनी को देश से बाहर निकाल देने की डीगें भरते हैं वहां दूसरी ओर कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता करने में तत्परता दिखाते हैं. उनके प्रति अपने विचार जाहिर करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "यह श्री फर्नांडीज की दुमुंही नीति व जनता सरकार की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आवभगत करने का ही नतीजा है जिसके कारण फ्रीमैन हमारी राष्ट्रीय नीतियों की भी आलोचना करने की हिम्मत करते हैं तथा विदेशी पूंजी के लिए भारत के दरवाजे खोलने की मांग करते हैं."

'भेल'-सीमेंस : विदेशी पूंजी विनियोग की ओर समझौतावादी सरकारी रुझान के कारण ही सरकारी प्रतिष्ठान भारत हेवीइलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ('भेल') की यह हिम्मत हुई कि वह पश्चिमी जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'सीमेंस' के साथ बिजली से संबंधित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए सहयोग करे जिन्हें पिछले 25 वर्ष से 'भेल' ही बना रहा था. इस सहयोग के पीछे यह बहाना बनाया गया कि इससे इन वस्तुओं के उत्पादन में तकनीकी उन्नति होगी. इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए सीटू के महासचिव ने कहा कि "इस प्रस्तावित समझौते मे सीमेंस ने साफ कह दिया है कि इस सहयोग से होने वाले सारे लाभ तकनीकी, आर्थिक इत्यादि—सीमेंस कंपनी को ही होंगे और उत्पादित चीजें भी ज्यादातर उनकी ही होंगी. इन होने वाले लाभों की एवज में इस कंपनी ने ऐसा कोई ठोस वायदा नहीं किया है जिससे कि वे अपनी उन्नत तकनीक को कभी 'भेल' को दे देंगे. अगर यह समझौता अमली रूप में लाया गया तो भारत में बिजली का उत्पादन न केवल कई गुना महंगा हो जाएगा बल्कि पूरी तरह से 'सीमेंस' पर निर्भर हो जाएगा."

बकालत : इंदिरा गांधी सरकार विश्व बैंक की धमकियों के आगे पहले ही झुक गई थी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवभगत कर रही थी. अपनी हैरानी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि "नई जनता सरकार ने भी जो कि जनतंत्र की हिफाजत के नारे पर सत्ता में आई थी, देश की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय

[शेष पृष्ठ 29 पर]

मजदूर वर्ग के संघर्षों में सीटू हमेशा अगुवा

सीटू सचिव कामरेड एस.के. पंधे द्वारा मद्रास में 11 से 15 अप्रैल को हुए चौथे सम्मेलन में पेश की गई कार्य और संगठन की रिपोर्ट के कुछ अंश

सी. आई. टी. यू. के सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने सीटू के चौथे सम्मेलन में तीसरे सम्मेलन के बाद की सीटू के 'कार्य और संगठन की रिपोर्ट' प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में कामरेड पंधे ने कहा कि "बम्बई सम्मेलन के बाद से सीटू हमेशा मजदूर वर्ग के संघर्षों में अगुवा रहा है और मजदूरवर्ग की एकता का जोरदार हिमायती रहा है. सीटू के झण्डे के तले मजदूर वर्ग के बढ़ते हुए संघर्षों से नित नये वर्ग संघर्ष की परिधि में आ रहे हैं. फलस्वरूप इस दौरान सीटू का कई दिशाओं में विकास हुआ है."

जिम्मेदारियाँ : सीटू की गतिविधियों से हांसिल अनुभवों को मध्येनजर रखते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "इस दौरान के अपने तजुर्बों से हमने यह सीखा है कि जब तक हम अपने संगठन को मजबूत नहीं बनाएं तथा अपने काम करने के तरीकों में सुधार नहीं करते, तब तक हम आज की अनुकूल हालत का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे. पिछले चार सालों में सीटू के प्रभाव के बढ़ने से मजदूर वर्ग की आशाएं भी बढ़ी हैं इस प्रकार हमारे ऊपर और अधिक जिम्मेदारियां आ गयी हैं."

कामयाब : वर्किंग कमेटी की मीटिंगों के बारे में कामरेड पंधे ने बताया कि "बंबई सम्मेलन के बाद वर्किंग कमेटी की पांच बैठकें हो चुकी हैं जिनमें से दो जनरल कांउसिल की बैठकों से ठीक एक दिन पहले हुई थी." इनमें से दो बैठक इमरजेंसी के दौरान हुईं. इन बैठकों की कार्यवाहियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि "इन दो बैठकों से सदस्यों को विभिन्न राज्यों के हालात पर जानकारी हासिल हुई. इन मीटिंग में सदस्यों द्वारा रखी गयी रिपोर्टों से जाहिर था कि सरकार द्वारा सीटू पर कई तरह की पाबन्दियां लगाने के बावजूद सीटू यूनियनें मजदूरों से नजदीकी सम्बन्ध बनाए रखने तथा उन्हें विभिन्न मुद्दों पर आगे लाने में कामयाब रही है."

जनरल कांउसिल : इसकी बैठकों के बारे में सीटू सचिव ने बताया "1976 के दौरान आपात्काल के कारण जनरल कांउसिल की कोई मीटिंग न हो पाई क्योंकि सीटू के संविधान के अनुसार एक साल में कम से कम एक मीटिंग लाजमी है, इसलिए जनरल कांउसिल के सदस्यों से इस साल मीटिंग न करने की स्वीकृति ले ली गई थी." इमरजेंसी के बाद जनरल कांउसिल की तीन बैठकें हुईं, एक कलकत्ता में [18 से 21 अगस्त 1977], दूसरी दिल्ली में [21 और 22 नवंबर, 1978] और तीसरी मद्रास में [11 अप्रैल 1970] चौथे सम्मेलन से तुरन्त पहले.

उद्योग स्तर पर तालमेल : सीटू केन्द्र को उद्योग स्तर पर गतिविधियों के तालमेल पर अधिक ध्यान देना पड़ा क्योंकि कुछ उद्योगों में देशव्यापी संघर्ष चल रहे थे. इससे प्राप्त अनुभवों की चर्चा करते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "उद्योग स्तर पर गतिविधियों के तालमेल से हम अपने क्रियाक्षेत्र को नित नए क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं जबकि एक ओर पूंजीपति वर्ग व सरकार आर्थिक मामलों में एक रूप नीतियां अपनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ऐसी हालत में मजदूर वर्ग के लिए भी यह जरूरी है कि शोषक वर्ग की ओर से आने वाली इस चुनौती का अधिक समन्वित ढंग से मुकाबला करे."

"मजदूरवर्ग की बढ़ती हुई चेतना के साथ उसकी यह ललक भी बढ़ रही है कि मालिकों पर अधिक दबाव डालने के लिए पूरे उद्योग के स्तर पर कदम उठाए जाएं. कई यूनियनों की ओर से यह मांग आ रही है कि उनके उद्योगों में अखिल भारतीय समन्वय समितियां बनाई जाएं."

"अपनी सीमाओं के बावजूद सीटू केन्द्र कुछ उद्योगों में समन्वय की दिशा में पहलकदमी कर पाया है." उन्होंने इस्पात, कोयला, गोदी व बंदरगाह, बागान, सड़क परिवहन, हेवी इलेक्ट्रीकल्स, चटकल, रबड़ व टायर, और रेलवे उद्योगों में इस दिशा में किए काम का विस्तार से ब्यौरा पेश किया.

कानूनी सहायता : विक्टिमाईज किये गये रेलवे मजदूरों को कानूनी सहायता देना जारी रहा और मई 1975 से निलम्बन आदेशों को खारिज करते हुए रेलवे मजदूरों के हक में फैसले होने लगे. ज्यादातर मामलों में रेलवे अधिकारियों ने फैसलों को नहीं माना और अपीलें दायर करनी शुरू कर दी थी. इन पैदा हुई दिक्कतों को बताते हुए कामरेडपंधे ने बताया कि "इसीलिए कानूनी सहायता के काम को जारी रखना पड़ा, फलस्वरूप नए केस नहीं लिए जा सके. इस फैसले के बावजूद 35 मामलों को जब कर्मचारियों के हक में घोषित किए गए फैसलों से प्रेरित होकर विकटमाईज किए गए रेलवे कर्मचारी अन्य मामलों के लिए आए सहायता देनी पड़ी. इस तरह 28 मामले जिन्हें रेलवे के वकील के आश्वासनों की बुनियाद पर वापस ले लिया था उन्हें पूरी तरह से दायर करना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों ने आश्वासनों को मानने से इन्कार कर दिया था."

राज्य कमेटियां : राज्य कमेटियों से प्राप्त की गई रिपोर्टों के आधार पर राज्य कमेटियों की गतिविधियों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए कामरेड पंधे ने बताया कि "केन्द्र का राज्य कमेटियों की गतिविधियों की नियमित रूप से रिपोर्ट नहीं मिलती हैं. कभी-कभी बैठकों के बाद जारी किए गए

[शेष पृष्ठ 12 पर]

सरकार द्वारा सीटू के साथ पक्षपात

[पृष्ठ 11 से आगे]

राज्य कमेटियों के प्रेस विज्ञापन सीटू केन्द्र को प्राप्त होते हैं."

सरकारी कमेटियां : कामरेड पंधे ने सरकारी कमेटियों में सीटू की भागेदारी का हवाला देते हुए कहा कि "इमरजेंसी के दौरान सभी त्रिपक्षीय मंचों से सीटू को दूर रखा गया था. सरकार की समूची परामर्श मशीनरी पर व्यापक राष्ट्रीय अपेक्स बोडी और इसकी सब-कमेटियां हावी थीं और केवल इंटक एटक और एच. एम. एस. के इंदिरा समर्थकों को ही इन बैठकों में बुलाया जाता था. सरकार द्वारा खास हिदायतें दी गई थीं कि उन यूनियनों को जो 20-सूत्री कार्यक्रम को नहीं मानती हैं, कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए."

"जनता सरकार के शासन में आने के बाद नए श्रममंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने 10 केन्द्रीय यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक अनौपचारिक बैठक बुलाई. सीटू के प्रतिनिधि, कामरेड पी. राममूर्ति और कामरेड एम. के. पंधे ने बैठक में भूतपूर्व इंदिरा सरकार की नीतियों की जबर्दस्त आलोचना की और उनको खत्म करने की मांग की. बैठक में श्रममंत्री ने त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने को स्वीकार किया जो 1971 के बाद त्याग दिया गया था.

"नई दिल्ली में 6-7 मई, 1977 को आयोजित किए गए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में औद्योगिक संबंधों, ग्रेच्युटी के सवाल, प्रबंध में मजदूरों की भागेदारी गलत मूल्य सूचकांक और असंगठित श्रमिकों की हालत के बारे में बातचीत की गई. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने जबरन जमा योजना को जारी रखने का और सरकार की 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस को बहाल करने में असफलता का कड़ा विरोध किया. सीटू की ओर से कामरेड पी. राममूर्ति और एम. के. पंधे ने डेलीगेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया, और कामरेड मोहन पुनमिया ने सलाहकार के रूप में भाग लिया. सम्मेलन में केन्द्रीय श्रममंत्री ने तीन कमेंटियों—[1] विस्तृत औद्योगिक संबंध कानून और भारतीय श्रम सम्मेलन की संरचना पर, [2] औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और [3] प्रबंध इक्विटी शेयरों, और प्रबंध में मजदूरों की भागेदारी पर बनाने की घोषणा की. उन्होंने असंगठित मजदूरों पर एक विशेष सम्मेलन बुलाये जाने पर भी रजामन्दी दिखाई."

विस्तृत औद्योगिक सम्बन्ध : सी. आई. टी. यू. ने इन तीनों कमेटियों में प्रतिनिधित्व किया. कामरेड पंधे ने बताया कि विस्तृत औद्योगिक संबंध कानून के लिए बनाई गई कमेटी ने सितम्बर 1977 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की. यह रिपोर्ट सर्व-सम्मत नहीं थी और "बाद में श्रम मंत्रालय ने जो विधेयक तैयार किया उसमें कई ऐसे मुद्दे शामिल किए गए थे जो कमेटी के पास पहले नहीं भेजे गए थे."

प्रतिनिधित्व : ग्रामीण असंगठित मजदूरों पर स्थाई कमेटी, खदानों में सुरक्षा पर पुर्नगठित कमेटी, कोयला खदानों में गैरहाजिरी रहने पर बनी कमेटी, सार्वजनिक उद्योगों पर गठित अध्ययन दल, राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर अध्ययन दल, राष्ट्रीय पुरस्कार कमेटी, भविष्य निधि संस्था के बोर्ड आफ ट्रस्टी, राष्ट्रीय श्रम संस्थान की जनरल कांउसिल आदि में सीटू का नामांकन किया गया. सीटू को अप्रत्यक्ष करों की जांच कमेटी, कम्पनियों और एम. आर. टी. पी. कानून की कमेटी, और रेलवे कंवेशन कमेटी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था. सीटू को शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता अभियान में ट्रेड यूनियनों के सहयोग लेने के लिए आयोजित सम्मेलन में, श्रमिक महिलाओं पर सम्मेलन और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के परिवार कल्याण कार्य पर गोष्ठी आदि में भी बुलाया गया.

पक्षपात : सीटू के प्रतिनिधित्व व नामांकन का खुलासा पेश करते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "इन नामजदगियों के बावजूद सरकार कई वैधानिक समितियों—कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रोजगार की केन्द्रीय समिति, न्यूनतम मजदूरी सलाहकारी समिति, केन्द्रीय बीड़ी उद्योग की समिति इत्यादि, से सीटू को अलग रख रही है. इन सब समितियों में अब भी इमरजेन्सी के दौरान सरकार से सहयोग करने वाली यूनियनों के प्रतिनिधि भरे पड़े हैं. सीटू ने समय-समय पर इन सवालों को सरकार के सामने उठाया है. किन्तु अभी तक इन दिशाओं में कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं. चाय, काफी, रबड़ इलायची जैसी वस्तुओं के बोर्डों पर सीटू को अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है. कई वायदों के बावजूद क्वायर बोर्ड को अब तक पुनर्गठित नहीं किया गया है. हमारे प्रतिनिधि कामरेड सुशीला गोपालन को भी इस बोर्ड के लिए अब तक नहीं बुलाया गया है."

"कई उद्योगों की विकास कांउसिलों में भी अब तक सीटू प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है. हमें उच्चस्तर पर इन मामलों को उठाना है जिससे कि हमारे विरुद्ध यह पक्षपात खत्म हो. कई राज्यों में राज्य श्रम सलाहकारी बोर्डों तथा अन्य समितियों में सीटू को नहीं लिया गया है. सीटू इस मामले की ओर भी अधिकारियों का ध्यान दिला रही है."

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : तीसरे सम्मेलन के बाद से सीटू के अन्तर्राष्ट्रीय संबंध लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी विस्तार से चर्चा करते हुए कामरेड पंधे ने कहा "हम कई ऐसी ट्रेड यूनियन जिनके साथ हमारे संबंध पहले से थे, अपने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में सफल हुए हैं तथा कई अन्य ट्रेड यूनियनों में संबंध बना पाए हैं." इनमें वियतनाम, जापान, रोमानिया, क्यूबा, श्रीलंका और चीन के ट्रेड यूनियन संगठन व ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस,

[शेष पृष्ठ 26 पर]

मजदूर वर्ग की एकता का प्रतीक
सीटू का चौथा सम्मेलन

मद्रास में आयोजित सी. आई. टी. यू. का चौथा सम्मेलन सीटू के इतिहास में एक स्मरणीय घटना है और सीटू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग के बढ़ते हुए संघर्ष का प्रतीक था. सी. आई. टी. यू. का चौथा सम्मेलन 4 साल के बाद हुआ. क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सम्मेलन बुलाना नामुमकिन था. सम्मेलन में 3,861 डेलागेटों तथा 50 बिरादराना डेलीगेटों ने जिन्होंने मजदूर वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर लगातार सघर्ष किये थे, भाग लिया. इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि 150 महिला डेलीगेटो ने इसमें भाग लिया.

सम्मेलन के समक्ष मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए सम्मेलन के पंडाल में वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई. वर्किंग कमेटी की बैठक के तुरत बाद जनरल काउंसिल की बैठक हुई.

सम्मेलन 11 अप्रैल को त्यागी वेंकटाचलम नगर में का. बी. टी. रणदिवे के झंडा फहराने और शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित करने के साथ शुरू हुआ. स्वागत समिति के अध्यक्ष कामरेड वी. पी. चिंतन ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मद्रास और आस-पास के इलाकों में सी. आई. टी. यू. की गतिविधियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि मद्रास में आयोजित सीटू सम्मेलन इस क्षेत्र में सीटू की गतिविधियों को और बढ़ावा देगा.

अपने अध्यक्षीय भाषण में कामरेड बी. टी. रणदिवे ने सीटू के तीसरे सम्मेलन के बाद के विकासों और घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से बताया. और मजदूर वर्ग के एकजुट होने की जरूरत का जिक्र किया.

सीटू के अध्यक्ष की ओर से कामरेड राममूर्ति ने शहीदों को श्रद्धांजलि और तीसरे सम्मेलन के बाद शहीद हुए साथियों के बारे में शोक प्रस्ताव पेश किए. सम्मेलन में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा कामरेड माओ स्ते तुंग का. चु तेह तथा का. चाऊ एन लाई को श्रद्धांजली अर्पित की गई. एक प्रस्ताव द्वारा कामरेड ए. के. गोपालन तथा भारत में विभिन्न आंदोलनों के महत्वपूर्ण नेताओं को श्रद्धांजली अर्पित की गई.

सी. आई. टी. यू. के महा सचिव कामरेड राममूर्ति ने अपनी जनरल रिपोर्ट में मजदूर वर्ग की एकजुट कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करते हुए सीटू के एकजुट आंदोलन के निर्माण और एकजुट संघर्ष से प्राप्त महत्वपूर्ण अनुभवों का वर्णन किया. उन्होंने जनता सरकार की आर्थिक नीतियों की चर्चा की और इन नीतियों के विरुद्ध एक मजबूत आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया.

कामरेड एम. के. पंधे ने अपनी 'कार्यवाहियों तथा संगठन' की रिपोर्ट पेश की और सीटू ने किस तरह से अनेक क्षेत्रों में प्रगति की इसका वर्णन किया.

विभिन्न देशों की कई ट्रेड यूनियन संगठनों ने सीटू सम्मेलन के लिए बधाई संदेश भेजे और सभी डेलीगेटों ने बड़े उत्साह के साथ इन संदेशों का तालियों के साथ स्वागत किया. वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ कामर्स और ट्रड यूनियन इंटरनेशनल आफ ट्रांसपोर्ट एड फिशरीज से संदेश प्राप्त हुए हैं. सोवियत संघ, चीन इटली, फ्रांस, यूगोस्लाविया, जनवादी गणराज्य कोरिया, मौरीशस, ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनों से भी संदेश प्राप्त हुए थे. कुछ केंद्रीय संगठन जैसे यू. टी. यू. सी., रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोशियशन, बी. एम. एस., आल इंडिया यूनिवर्सिटी एंप्लाईज कान्फेडरेशन ने भी संदेश भेजे थे.

[शेष पृष्ठ 14 पर]

सीट अध्यक्ष कामरेड बी. टा. रणदिवे

मजदूर किसान एकता और मजबूत

[पृष्ठ 13 से आगे]

रोमानिया की जनरल कान्फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन ने एक शिष्ट मंडल भेजा था जिसमें कामरेड स्तान जार्जी जी. आर. टी. यू. सी. के कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय विभाग जी. आर. टी. यू. सी. के सदस्य कामरेड हेंटर गावरिला थे. समाजवादी गणराज्य वियतनाम के दूतालय के प्रथम सचिव ने भी सम्मेलन में भाग लिया तथा वियतनाम फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन का संदेश दिया. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कामरेड आबजरवर के रूप में हाजिर हुए. एटक की ओर से कामरेड के. टी. के. थगमणी ने सम्मेलन को बधाई दी और भारतीय श्रमिक वर्ग की संयुक्त आंदोलन की और सफलताओं की कामना की. अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत संसद सदस्य, उपाध्यक्ष, ने अभिनंदन करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मजदूर और किसान एकता और मजबूत होगी. स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष का. एम. ए. बेबी ने छात्रों की ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ एकता व्यक्त की.

पश्चिम बंगाल सरकार के श्रममंत्री कामरेड कृष्णपद घोष ने सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रकाशित सोवेनियर का उदघाटन किया जिसे स्वागत समिति ने प्रकाशित किया था. इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में बताया और इसकी चर्चा की कि सरकार मजदूर वर्ग के संघर्ष के पूर्ण हित में रही.

सम्मेलन ने केरल में आर. एस. एस. के गुंडों द्वारा दो कामरेडों की हत्या पर प्रस्ताव पास किया. का. मनोरंजन राय ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के साथ बंधुत्व का प्रस्ताव रखा जिसका का. मोहन पुनमिया ने समर्थन किया. यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ.

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव कमेटी सम्मेलन में पेश किए गये प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए बनाई. जिसके कामरेड मोहन पुनमिया, संयोजक, का. समर मुकर्जी, का. एम. के. पंधे, का. विश्वनाथ मेनन, का. एस. एस. बोस, का. के. रविन्द्रनाथ, का. मदन फर्नांडीस, का. प्रभाकर सम्भागिरी, का. एन. प्रसाद राव और का. विरेन राय थे. सम्मेलन में एक क्रेडेंशियल कमेटी भी बनाई गयी. जिसके का. नलाशिवम संयोजक, का. शांति घटक, का. विश्वेश्वर गांगुली का. सुहृद मलिक चौधरी, का. डी. डी. शिराली, का. ओ. के. जोसफ, का. प्रकाश घोष और नवीराजन एफिलियेशन फार्मों तथा डालगेट फार्मों की जांच करने के लिए सदस्य थे.

लगभग 40 डेलीगेटों ने बहस में हिस्सा लिया. और एमरजेंसी के दौरान तथा उसके बाद संयुक्त संघर्ष के बारे में अपने अनुभव बताए और एकजुट आंदोलन को आगे बढ़ाने व विकसित करने के लिए कदम उठाने का कदम उठाने की ,आवश्यकता पर जोर दिया. कई वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार सीटू ने इमरजेंसी के दौर में मजदूर वर्ग के मुद्दों पर संघर्ष करके अपनी ताकत और मजबूत बनाई तथा इटक और एटक के नेतृत्व के विश्वासघात के खिलाफ लड़ाई लड़ी. कई वक्ताओं ने सीटू के नेतृत्व में तालाबंदी और बेरोजगारी के खिलाफ चलाए गए लंबे आंदोलन का वर्णन किया. कुछ ने मजदूर-किसान एकता को मजबूत बनाने की और मजदूरों में इस एकता की जबरदस्त जरूरत के प्रति जागृति पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि काम और निर्वाह की हालतों पर बुर्जुआ प्रहार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा सके.

कई वक्ताओं ने आरक्षण नीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह किस प्रकार मजदूर वर्ग की एकता को खतरे

[शेष पृष्ठ 23 पर]

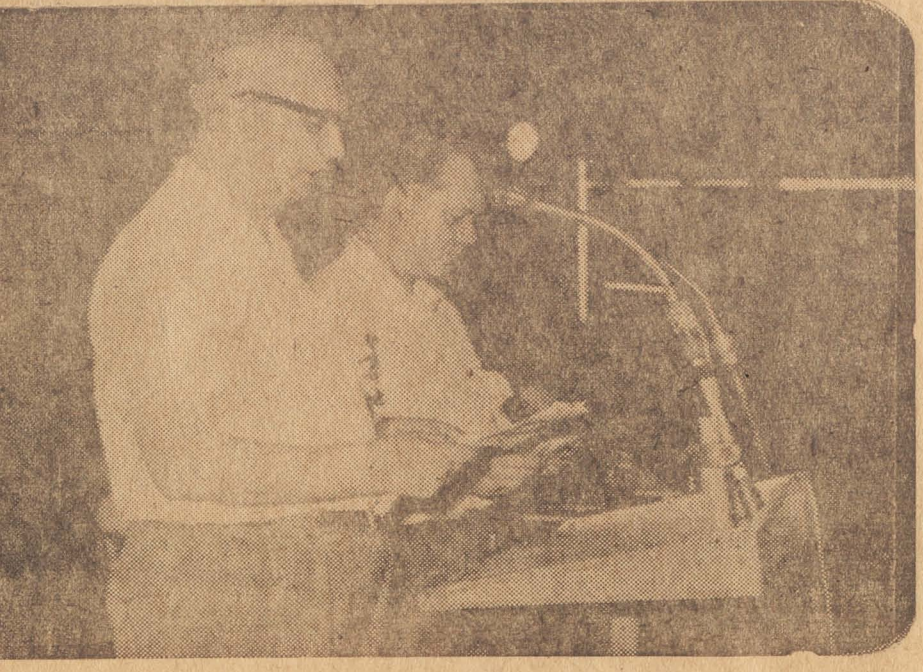

रोमानियन डेलीगेट कामरेड स्तान जार्जी (बांएं) व कामरेड हेंटर गावरिला

प्रस्ताव

मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भारतीय मजदूर वर्ग के कार्य पर

सीटू का यह चौथा सम्मेलन देश में एमरजेंसी के बाद की अशुभ राजनीतिक घटनाओं पर गंभीरता से गौर करता है और मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा ट्रेड यूनियन चलाने की आजादी को बनाये रखने के लिए सारी स्थिति को वस्तुगत तरीके से समझने की कोशिश करे.

यह सम्मेलन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि जनता सरकार की नाकामियां तानाशाही ताकतों को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद पहुंचा रही है. जनता सरकार अपने चुनावी वायदों को जैसे भूल ही गयी है. कांग्रेस की उन्हीं पुरानी नीतियों पर चलते हुए वह न केवल मेहनतकश अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है बल्कि उसने करों का भारी बोझ भी उन पर लाद दिया है, जबकि इजारेदार पूंजीपति को वह लगातार फायदा पहुंचा रही है. जनता सरकार के खिलाफ लोगों के असंतोष का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही की ताकतें एमरजेंसी के दौरान अपने काले कारनामों पर परदा डालने और अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं. जनता पार्टी की अंदरूनी कलह और उससे उत्पन्न अस्थिरता का वातावरण भी तानाशाही ताकतों की मदद कर रहा है. वे सारी स्थिति को गडबड़ा कर सत्ता में वापस आने की फिराक में हैं.

यह सम्मेलन चिंता के साथ इस सचाई पर भी गौर करता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रतिक्रियावादी शक्तियां जनता पार्टी और सरकार के अंदर ऐसी स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जहां वे इन दोनों को अपने इशारों पर नचा सकें. अगर प्रतिक्रियावादी संघी ताकतों का ऐसा दबदबा कायम हो गया तो जनता सरकार का धर्म निरपेक्षता का दावा व्यर्थ हो जायेगा और तानाशाही की ताकतों के खिलाफ संघर्ष के कारण जनता पर जो असर वह कायम कर सकी है वह भी नष्ट हो जायेगा. जनता पार्टी के भीतर इन प्रतिक्रियावादी ताकतों का जिन धर्म-निरपेक्ष और लोकतांत्रिक तत्वों ने विरोध किया है, यह सम्मेलन उसका स्वागत करता है. इसके साथ ही वह भारत के मजदूर वर्ग को चेतावनी देता है कि इन घटनाओं के बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे और इसलिए इन पर मजदूर वर्ग को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए.

यह सम्मेलन इस बात पर भी गौर करता है कि जनता सरकार की नीतियां तानाशाही-विरोधी शक्तियों की एकता को घटा रही हैं. मजदूरों और कर्मचारियों के संगठित तबके जो कि अब हिंदुस्तान में एक जबरदस्त ताकत बन चुके हैं. सरकार की इस नीति का मुकाबला कर सकते हैं और लोकतंत्र की रक्षा और उसका विस्तार कर सकते हैं साथ ही ट्रेड यूनियनों की जुझारू ताकतों के साथ मिलकर वामपंथी तथा जनवादी एकता कायम कर सकते हैं. अपने इस संघर्ष में उन्हें किसानों, छात्रों और मेहनतकश जनता के सभी तबकों के बीच बढ़ती हुई एकता से मदद मिलेगी. वामजनवादी एकता हासिल करने के इस संघर्ष में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकारें सीधे-सीधे मदद देंगी.

भारतीय मजदूर वर्ग, विशेष मजदूरों और कर्मचारियों के संगठित तबके को भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरे को महसूस करना चाहिए. उसे जनता के जनवादी अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा और विस्तार करने वाले एक कार्यक्रम के आधार पर वाम तथा जनवादी शक्तियों के बीच एकता कायम करने के संघर्ष में जुट जाना चाहिए. यह सम्मेलन उनका आह्वान करता है कि वे पूरी गंभीरता के साथ इस महान कार्य का बीड़ा उठायें और इसे संभव बनाने में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता को अडिग बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करें.

मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्यवाहियों पर

सीटू का यह चौथा अधिवेशन समान हित के मुद्दों पर भारत के मजदूर वर्ग के अनेक संघर्षों में उभर रही एकता का स्वागत करता है. मजदूर वर्ग के ज्यादा से ज्यादा हिस्से संयुक्त संघर्षों में भाग लेकर पूंजी के प्रहार विरुद्ध ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक मजबूत ताकत के रूप में परिणत कर रहे हैं.

अनेक संयुक्त कार्यवाहियों के माध्यम से मजदूरों की एकता की छटपटाहट व्यक्त होती है. ट्रेड यूनियन अधिकारों और समानहित की मांगों पर ट्रेड यूनियनों का 18 सितंबर 1977 का अखिल भारतीय अधिवेशन, पब्लिक सेक्टर यूनियनों के हैदराबाद और दिल्ली में अधिवेशन और साथ ही 19 नवंबर 1978 को आयोजित औद्योगिक संबंध विधेयक के अखिल भारतीय अधिवेशन-देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की संयुक्त ताकत के स्पष्ट प्रतीक थे. 20 नवंबर 1978 के दिन संसद पर मजदूरों का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ जिसमें हमारे

[शेष पृष्ठ 17 पर]

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बारे में

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सरकारें जिन नितांत कठिन परिस्थितियों में जिस तरह काम कर रही हैं और उन्होंने जो सफलताएं हासिल की हैं उनके लिए सीटू का यह सम्मेलन गहरी प्रशंसा प्रकट करता है. पश्चिम बंगाल में 22 महीनों तथा त्रिपुरा में 14 महीनों के अनुभवों से यह सिद्ध हो गया है कि इन सरकारों की लोकप्रियता और सम्मान केवल इन्हीं दो राज्यों के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के के मजदूर वर्ग और लोकतंत्र प्रेमी जनता में बढ़ी है. सम्मेलन का विचार है कि जनता के लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा में अविचलित रहकर यह समूचे भारत में वाम और लोकतांत्रिक शक्तियों के विकास के लिए एक प्रेरक का काम कर रही हैं.

सम्मेलन को इस बात पर गर्व है कि पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मजदूरवर्ग तथा जनता को पूर्ण लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त हैं और वे न्यायोचित मांगों को लेकर किए जाने वाले अपने सभी संघर्षों में इन दोनों सरकारों की पूरी सहानुभूति पाते हैं. दूसरे राज्यों में स्थिति ऐसी नहीं है. पश्चिम बंगाल में जूट, इंजीनियरी तथा सूती कपड़ा मजदूरों को हाल में जो फहयाबियां मिली हैं वे उनके संघर्ष के दौरान इन दोनों सरकारों से मिले समर्थन के प्रमाण हैं. इन दोनों राज्यों में लोगों को पंचायतों के जरिये, आंचलिक स्वायत्त निकायों जैसे दार्जिलिंग में नेपाली भाषियों के लिए और त्रिपुरा में जन जातीय आबादी आदि के लिए, अधिक शक्तियां मिल रही हैं इन दोनों सरकारों ने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता तथा आर्थिक साधन स्रोतों की मांग को बुलन्द किया जिसका अब तक देश व्यापी प्रभाव पड़ा है और जिसके मारत के भविष्य का पुनर्निर्माण करने में बहुत दूर तक प्रभाव पड़ेगा.

भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक सीमित पैमाने पर बेकारी राहत की व्यवस्था की. पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा सरकारों ने फसली काम के बाद के ठाले के दिनों के लिए, जबकि कोई काम नहीं मिलता, गांवों में गरीब जनता की मदद के लिए बड़े पैमाने पर "काम के लिए भोजन" की योजनाएं बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की हैं. गरीब और मझौले किसानों के लिए इन योजनाओं तथा अनेक दूसरे आर्थिक उपायों, जैसे लेवी और जमीन की लगान से छूट, बर्गदारों के अधिकारों की खतौनी "वर्ग प्रचालना" और ऐसे ही दूसरे उपायों से गांवों की आम जनता में भरपूर उत्साह पैदा हुआ है.

पश्चिम बंगाल की जनता और सरकार ने अभूतपूर्व बाढ़ का जिस तरह मुकाबला किया, प्रभावित लोगों को जिस तरह बचाया और जिस तरह राहत जुटाई और उसका जैसे वितरण किया और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों का जिस तरह गठन किया उसके लिए उनकी बहुत अधिक सराहना व प्रशंसा हुई है. सम्मेलन की राय में ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि वाममोर्चा सरकार को आम जनता का विश्वास प्राप्त था और वह उस संकट का मुकाबला करने के लिए इस प्रकार का सक्रिय सहयोग जुटाने में समर्थ थी. इस कार्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका पेश की.

सम्मेलन ने यह नोट किया है कि इन दोनों सरकारों की बढ़ती हुई लोकप्रियता और सम्मान के कारण शोषक वर्गों और दिवालिया राजनीतिक पार्टियों के भीतर शत्रुता ओर विरोध भी फैला है. यही कारण है कि विधान सभा के भीतर और बाहर दोनों जगह वाममोर्चा सरकारों की छवि को बिगाड़ने, इन सरकारों के कामकाज में हर तरह के अड़ंगे खड़े करने, लोगों की आपदाओं और कष्टों का फायदा उठाने और अराजकता तथा तकरार को प्रोत्साहन देने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं.

सम्मेलन लोगों को इन विघटनकारी शक्तियों के खतरों से आगाह करता है और मजदूर वर्ग और लोकतंत्र प्रेमी आम जनता को इस बात के लिए आह्वान करता है कि वे उनकी इन चालों का अच्छी तरह पर्दाफाश करें और भारत में वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों की मजबूत सुरक्षा चौकियों की तरह इन दोनों सरकारों की दृढ़ता से रक्षा करें.

वियतनाम के बारे में

सीटू का यह चौथा संमेलन वियतनाम की भूमि पर चीन सरकार की फौजों द्वारा चढ़ाई की कठोर शब्दों में निंदा करता है. सम्मेलन की राय में यह कार्रवाई बड़े राष्ट्र की उग्र राष्ट्रीयता की मिसाल है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के तौर-तरीकों का उल्लंघन किया गया हैं. दुनिया को पंचशील के सिद्धांतों के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता प्रदान करने में चीन ने एक प्रमुख भूमिका निभायी है. इसे देखते हुए उसके नेताओं की यह आक्रामक कार्रवाई और भी ज्यादा निंदनीय तथा धक्का पहुंचाने वाली हो जाती है.

यह संमेलन वियतनाम की जनता के प्रति गहरी दोस्ती और एकजुटता का इजहार करता है. उसे उन्हीं लोगों से लड़ने पर मजबूर होना पड़ा जिनके साथ दोस्ती और एकता पर वह हमेशा नाज करती आयी थी. वियतनाम के लोगों ने जिस कामयाबी के साथ अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की उसके लिए सम्मेलन उन्हें मुबारकबाद देता है. इसके साथ ही इस थोपी गयी लड़ाई में उन्हें जो भारी नुकसान उठाना पड़ा उसके लिए सम्मेलन दिली हमदर्दी का इजहार करता है.

यह संमेलन इस बात पर संतोष प्रकट करता है कि चीन सरकार ने वियतनाम की भूमि से अपनी फौजों को पूरी तरह वापस बुलाने की घोषणा कर दी है. हालांकि फौजों की वापसी के इस काम में कुछ कमियां रह सकती हैं और मुमकिन है कि इसे पूरी तरह अंजाम न दिया जा सके, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कदम है जिसका सभी

[शेष पृष्ठ 21 पर]

तमिलनाडु के मजदूर वर्ग को बधाई पर

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र का चौथा सम्मेलन तमिलनाडु के मजदूर वर्ग को सीटू के पिछले सम्मेलन से लेकर अब तक अनेक बहादुर राना संघर्षों के लिए बधाई देता है. खासतौर से पिछले दो वर्षों के दौरान उन्होंने जोरदार पुलिस दमन और प्रबंधकों के भाड़े के टट्टुओं और गुंडों के हमलों के बावजूद बहुत ही कड़वे और लम्बे संघर्ष किये हैं. टी. वी. एस. के मजदूरों ने सीटू के झंडे के नीचे लम्बा संघर्ष चलाया जिसमें जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुले आम स्वीकार किया था प्रबंधकों ने भाड़े के गुंडे रख रखे थे और उन्होंने मजदूरों पर हमले किये. टी. वी. एस. के प्रबंधकों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सामने जो समझौता किया था उससे मुकर गये फिर भी तमिलनाडु सरकार ने न तो इस समझौते को लागू कराने के लिए कोई कदम उठाया न ही प्रबंधकों के गुंडों के खिलाफ कोई कदम उठाया. इसके विपरीत इनमें सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगाकर मजदूरों को अपने वैध ट्रेड यूनियन संघर्षों को चलाने से भी रोक दिया और प्रबंधकों के कहने में आकर इसने बहुत से मजदूरों के खिलाफ झूठे मुकदमें दायर किए.

तमिलनाडु की ट्रेड यूनियनों और विरोधी पार्टियों ने टी. आई. साइकिल फैक्टरी के मजदूरों पर मजदूरों में से अपने मन के "प्रतिनिधि" छांटकर उनके साथ किए गए मजदूर विरोधी समझौते लादने के विरोध में एक राज्य व्यापी हड़ताल की. प्रतिनिधियों ने पहले से मौजूद यूनियनों को दर किनार कर दिया था. शासक दल ने मजदूरों और आम लोगों और दूकानदारों पर हमला करने के लिए अपने दरिंदों का, जिन्हें "श्वेत ब्रिगेड" के रूप में तैयार किया गया था, इस्तेमाल किया. इन हमलों में पुलिस के साथ सांठ-गांठ की गई थी. इस तरह की अनेक मिसालें दी जा सकती हैं.

इन अविचलित संघर्षों में, जिसमें सीटू अगले मोर्चे पर थी, अनेक मामलों में मजदूरों को खासी सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता मिली. इसकी सबसे ताजी मिसाल सिमको मजदूर संघर्ष है जो साढ़े चार महीने तक चलता रहा और जिसको दबाने की सरकार ने कोशिश की थी. इसका श्रेय मजदूरों के दृढ़ संकल्प को और सभी मजदूर यूनियनों और तमिलनाडु विधान सभा में सभी विरोधी पार्टियों द्वारा मिले समर्थन को है जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को असंभव बना दिया था, कि सरकार ने लाचार होकर प्रबंधकों से कुछ सुविधाएं दिलानी पड़ी. इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों के वेतन में 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 200 से अधिक मजदूरों की नौकरियां पक्की की गई.

सीटू राज्य बिजली बोर्ड, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स, सदर्न, स्विच गीयर कन्याकुमारी जिला में बागान, कोयम्बटूर और मदुरै की सूती मिलों, तिरुची के 'भेल'

[शेष पृष्ठ 20 पर]

संयुक्त कार्यवाही

[पृष्ठ 15 से आगे]

देश के मजदूर वर्ग के सभी तबके शामिल थे.

स्थानीय और औद्योगिक स्तरों पर अनेक ऐसी हड़तालें हुई हैं जिनमें सभी ट्रेड यूनियनों ने हाथ मिलाया. नतीजा यह कि प्रबंधकों तथा सरकार को मजदूरों की मांगें मानने पर मजबूर होना पड़ा.

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन संयुक्त संघर्षों में हिस्सा लेने वाले सभी मजदूरों को सभी मजदूरों को सीटू का यह चौथा अधिवेशन गर्म जोशी के साथ मुबारकवाद देता है. सीटू सभी ट्रेड यूनियनों और मजदूरों से अपील करती है कि वे अपनी संयुक्त कोशिशों को इस तरह दुगुना-चौगुना करें कि मजदूरों के आगे आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा सके :

वेतन जाम के खिलाफ और जरूरत पर आधारित वेतन के पक्ष में;

जीवनयापन के मूल्य में वृद्धि की सौ फी सदी भरपायी के पक्ष में;

सबके लिए बोनस और मौजूदा बोनस फार्मूले का मजदूरों के पक्ष में बहुत ज्यादा सुधार के पक्ष में;

देहाती और शहरी बेरोजगारों के लिए काम करने का अधिकार अथवा बेकारी भत्ते के पक्ष में;

मिल बंदी और छंटनी पर पाबंदी के पक्ष में;

जाली मूल्य सूचकांक में पूरी तरह सुधार के पक्ष में;

सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन संबंधी समझौता वार्ताओं में सार्वजनिक उद्यम के ब्यूरो की दखलंदाजी के खिलाफ;

औद्योगिक संबंध बिल तथा अन्य संबद्ध बिलों को खारिज कराने के लिए;

गुप्त मतदान के द्वारा ट्रेड यूनियनों की स्वीकृति के लिए;

ट्रेड यूनियन संघर्षों के दौरान पुलिस दमन और गुंडा गिरोह के हमलों के खिलाफ;

महिला कामगारों के अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा के लिए.

एच. एम. एस., एच. एम. पी. और अन्य संगठनों के बंबई में हुए एकजुटता अधिवेशन के ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुटकता पर विशेष बल दिया गया है. सीटू एकता के लिए उभर रही इस भावना के संदर्भ में उसका स्वागत करती है.

एक उद्योग में एक ट्रेड यूनियन कायम करना तुरंत तो संभव नहीं है, पर सीटू का विचार है कि यू. सी. टी. यू. जैसे व्यापक संगठन अनेक ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फैडरेशनों के संयुक्त आंदोलन खड़ा करने में दूरगामी प्रभाव डालेंगे. मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सीटू अन्य संगठनों से सहयोग करके मजदूर वर्ग की ऐसी एकता कायम करने में कुछ भी उठा न रखेगी.

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की वाम मोर्चा

ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता का अपार महत्त्व

[पृष्ठ 6 से आगे]

गुप्त मतदान : इस बारे में सीटू की विचारधारा को व्यक्त करते हुए कामरेड रणदिवे ने का, "सीटू और दूसरे अनेक ट्रेड यूनियन केन्द्रों ने इस बात की मांग की है कि ट्रेड यूनियन की मान्यता का फैसला सभी मजदूरों के गुप्त मतदान से किया जाय. हम मजदूरों द्वारा लोकतांत्रिक मतदान के आधार पर एक उद्योग में एक यूनियन का समर्थन करते हैं." लेकिन, जनता सरकार, जिसे लोकतंत्र का रक्षक समझा जाता है, ने इस लोकतांत्रिक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है. औद्योगिक संबंध विधेयक में भी मान्यता का फैसला करने के लिए मतदान को अनिवार्य सिद्धांत नहीं माना गया है.

प्रचार : सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष ने इस सिलसिले में बदनामी फैलाने वाले प्रचार का जिक्र किया. बंबई में एक एक मालिक पर भाड़े के गुंडों द्वारा हमले को, "पूंजीवादी प्रेस, पूंजीपतियों और दूसरे आम शोषकों और उनके भाड़े के टट्टुओं ने ट्रेड यूनियनों की निन्दा शुरू कर दी और कहने लगे कि यह जानलेवा हमला ट्रेड यूनियनों की होड़ के कारण हुआ है." इसका कारण बताते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "अधिकांश मामलों में इसकी वजह यह है कि प्रबंध समितियां, मालिक और शासक पूंजीवादी पार्टियां स्थापित यूनियनों का मुकाबला करने के लिए अक्सर बदमाशों का इस्तेमाल करती हैं. उन्हें विशेष सुविधायें देती हैं. और उनकी यूनियनों को मान्यता देती हैं और संगठित मजदूरों को डराने धमकाने के लिए उनके गिरोह को संरक्षण प्रदान करती हैं. आंदोलन के सामने यह एक नया खतरा है. समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को संगठित होकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए."

गठजोड़ : "ट्रेड यूनियन आंदोलन का किसानों और खेतिहर मजदूरों के आंदोलन से कट जाना, देहाती आम जनता की मांगों को लोकतंत्र और समाजवाद के लिए हमारे संघर्ष के अनिवार्य हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने में हमारी नाकामी ने सिर्फ इन दोनों आंदोलनों को ही कमजोर नहीं बनाया है बल्कि यह दोनों के लिए अब नये खतरे भी पैदा कर रही है."

यह बताते, हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "जमींदार और पूंजीपति और उनके प्रवक्ता किसानों और कृषि-मजदूरों को निम्नतम जीवन स्तर पर ठेल कर अब देहाती अवाम को शहरों के गरीब मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ उकसाने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं··· भाड़े के प्रोफेसरों को यह साबित करने के लिए खरीदा जाता है कि मजदूर वर्ग और कर्मचारी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग में आते हैं और किसानों का शोषण करते हैं.

जीवंत शक्तियां : इन दोनों शक्तियों को लोकतंत्र और समाजवाद की जीवंत शक्तियां कहते हुए उन्होंने कहा, "इन दोनों के बीच सक्रिय सहयोग और एका वाम मोर्चे और लोकतांत्रिक शक्तियों के निर्माण के लिए एक लीवर का काम करता है. यह बहुत अच्छा मौका है जब सी. आई. टी. यू. तथा हमारी ट्रेड यूनियनें अखिल भारतीन किसान सभा के साथ जो कि हमारे किसानों और खेतिहर मजदूरों की अनेक शानदार व्यापक लड़ाइयों में आगे रही है निकट सहयोग विकसित करें.

फसाद : जाति और धर्म के नाम पर मजदूर वर्ग के आंदोलन में बटवारे को अजनबी बताते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "ट्रेड यूनियनों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी सभी पुरातनवादी प्रवृत्तियों की खिलाफत करनी चाहिए और सांप्रदायिक तथा जातीय फसादों के खिलाफ लड़ना चाहिए. किसानों की मांगों की हिमायत के साथ इस बात से मजदूरों और ग्रामीण आम जनता के निकट एकता कायम होगी."

एक हिस्सा : मद्रास में कामगार महिलाओं के सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "सी. आई. टी. यू. को इस विशेष सम्मेलन को बुलाने का फैसला इस लिए लेना पड़ा कि यह देखा गया था कि कामगार महिलाओं की तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया जाता. सरकार उनके प्रति उदासीन है. मालिक उनसे वैर-भाव रखते हैं और यहां तक कि ट्रेड यूनियनें भी उनकी मांगों के प्रति उत्साह नहीं दिखाती. मजदूर वर्ग ने जो हड़तालें कीं उनमें इस बात की बहुत कम मिसालें आई जब कामगार महिलाओं की मांगों को प्रमुखता दी गई हो."

यह भी देखा गया है कि महिलाओं को यूनियनों में मुश्किल में ही कोई नुमाइंदगी मिलती है. कुछ तो यह भारतीय समाज की देन है. यह देखा गया है कि प्रसूति की सुविधाएं और कानून द्वारा निहित अन्य सुविधाएं देने से बचने के लिए श्रमिक महिला कामगारों की छटनी कर देते हैं. भारतीय व्यवस्था पर कटाक्ष कसते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "भारत जिसका एक पांव पूंजीवादी युग में है और दूसरा पिछले जमाने में. वह औरतों के प्रति भेद भाव से काम लें तो इसमे अचरज की कोई बात नहीं. ट्रेड यूनियन आंदोलन से इसे मजदूर वर्ग के संघर्ष का एक हिस्सा मान कर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी."

प्रेरणा : कामरेड बी. टी. रणदिवे ने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री और सी. आइ. टी. यू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु को बधाई

सरकारें जनवादी शक्तियों के लिए प्रेरणा

दी. उन्होंने कहा कि "पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारें प्राधिकारवाद के विरुद्ध संघर्ष में और लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत्र हैं." उन्होंने कहा कि एक करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला बाढ़ के सकंटपूर्ण दिनों में पश्चिम बंगाल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने जो एतिहासिक बहादुरी दिखाई उसे कोई भूल नहीं सकता. दलित जनों के संघर्ष के संबंध में उन्होंने कहा कि, "हमारी पश्चिम बंगाल सरकार का काम करने का ढंग दूसरी जगहों पर जनता और कांग्रेस (इ) की सरकारों के तरीके से या तमिलनाडु की सरकार या दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चल रही केरल की सरकारों द्वारा अपनाए गए तरीके से तीखा अलगाव रखता है. पश्चिम बंगाल एक मात्र ऐसा राज्य है जहां हड़ताल करने के अधिकार को पूरी मान्यता मिली हुई है और इसे राज्य के हस्तक्षेप के बिना अमल में लाने की छूट है".

आम मोर्चा : केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की एकजुट कार्यवाही ने एकता क लिए अभूतपूर्व वातावरण तैयार किया

जरूरत : इस समय एकता के एक अधिक और व्यापक आधार को जरूरत को बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारी

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे

सभी यूनियनों को यह याद रखना होगा कि हम सिर्फ एकता के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष और प्रतिरोध की एक नीति पर चलने

उठा सकते हैं, संगठित ट्रेड यूनियन प्रतिरोध ऐसी सभी काम व लोकतांत्रिक ताकतों को जो प्राधिकारवादी तानाशाही की वापसी के विरोध में खड़ी हैं, स्वतंत्र रूप से एक बिन्दु पर लाने का कार्य कर सकता है. इंदिरा गांधी से पैदा होने वाली चुनौती आज की स्थिति को देखते हुए इसका अपार महत्व है."

चुनौती : देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए का० बी. टी. रणदिवे ने कहा, "सी. आई. टी. यू. और ट्रेड यूनियन आंदोलन देश की सकंटपूर्ण राजनीतिक स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकती और कांग्रेस (इ) के प्राधिकारवादी शासन को पुनः हासिल करने की उद्धत चुनौती के प्रति आंख मूदें नहीं रह सकती. यद्यपि जनता पार्टी को बहुत बड़ा जनमत हासिल हुआ है पर चूंकि वह भी कांग्रेस की ही वर्ग नीतियों पर चल रही है इसलिए वह प्राधिकारवादी शक्तियों के विरुद्ध प्रभावशाली संघर्ष चलाने में नाकाम रही है वाम पंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों की एकता ही अकेली वह ताकत है जो जनता को एकजुट कर सकती है और तानाशाही के हमले को रोक सकती है और इसमें

तानाशाही का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ

है. इस एकता पर जोर देते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा, "सी. आई. टी. यू. सभी केंद्रीय यूनियन संगठनों, सभी कर्मचारी संगठनों, केंद्रीय व राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों और अध्यापकों तथा प्रोफेसरों के संघों को एकजुट होकर और एक आम श्रम नीति के लिए जोर डालने तथा सभी तबकों के हितों की रक्षा करने की मांग करता है. हमारी इच्छा है कि ये सभी संगठन तत्काल एक साथ मिलकर स्थिति का जायजा लें, मांगों और कानूनों के सवाल पर एक आम मोर्चा कायम करें और मालिकों को जता दें कि मजदूर आंदोलन एक और अविभाज्य है."

के लिए एकता कायम करते है; कि एकता के नाम पर हम पिट्ठुओं के साथ समझौता नहीं करते. हम चाहते हैं कि विभिन्न संगठनों को मजदूर सम्मिलित संघर्ष और अनुभव से एक आम नीति अपनाएं."

अपार महत्व : मजदूर वर्ग की सम्मिलित कार्यवाही और ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष का अपार महत्व है जो ट्रेड यूनियनों के दायरे से भी बाहर तक जाता है. इस पर और जोर देते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा "वर्तमान स्थिति में जब जनता सरकार की नीतियों से पैदा होने वाले आर्थिक असंतोष का फायदा इंदिरा गांधी और उनके हमदामन

पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारें काफी जोरदार भूमिका पेश कर रहीं हैं."

चेतावनी : कामरेड रणदिवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि "तानाशाही का खतरा समाप्त नहीं हुआ है" इसलिए इसके खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई चलाने के लिए "मजदूर वर्ग को इमरजेंसी के दौरान संविधान में शामिल किए तानाशाही ढांचे को खत्म करने की एकजुट होकर मांग करनी होगी."

कामरेड बी. टी. रणदिवे ने एकजुट संघर्ष की सफलता की कामना करते हुए कहा कि इस "सफलता का अर्थ होगा कि मजदूर वर्ग और जनता में अपने भविष्य का निर्णय करने की पहल पैदा होगी".

दमन के बारे में

सीटू का यह चौथा सम्मेलन इस बात पर गहरी चिंता प्रकट करता है कि भारत में मजदूर वर्ग को आये दिन पुलिस की गोलियों का और जनता पार्टी के शासन में मालिकों के भाड़े के गुंडों के पाशविक आक्रमण का निशाना बनाया जा रहा है और इन हमलों को ट्रेड यूनियन आन्दोलन को छिन्न-भिन्न करने तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों की स्वतंत्रता को कम करने का सोद्देश्य प्रयत्न मानता है.

जहां ये उपाय पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में, जहां पुलिस को ट्रेड यूनियन आंदोलन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई है और ट्रेड यूनियन गतिविधियों की स्वतंत्रता की पूरी रक्षा की गई है, चलाई जा रही नीतियों से तीखा विरोध रखते हैं, वहां दूसरे राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें इरादतन निर्वाचन के समय किये गये सभी वायदों को भुलाकार मजदूर वर्ग का दमन करने की नीति पर चल रही हैं और इससे यह जाहिर होता है कि कांग्रेस शासन द्वारा अपनाई गई नीति का आज भी बोल बाला है.

कानपुर की स्वदेशी काटन मिल में पुलिस नृशस गोलीबारी पर उतारू हो गई और ग्यारह मजदूरों की जान ले ली. बिहार के इस्पात नगर बोकारो में भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कं. लि. का एक मजदूर पुलिस की गोली से उस समय मारा गया जब मजदूर अपनी नौकरियों को पक्का कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे. उत्तर प्रदेश के पंत नगर में पुलिस की गोली से जितने मजदूर भून दिए गए वह एक नया रिकार्ड था. मध्यप्रदेश में राजहरा में बैला डिला आइरन ओर माइन्स में पुलिस ने बिल्कुल मनमाने ढंग से गोलियां चलाई और बहुत से मजदूरों को जान से मार डाला. फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, हिसार (हरियाणा) और पानीपत तथा दूसरे बहुत से स्थानों में पुलिस की गोलियों से और मालिकों के भाड़े के गुंडों के हमलों से बहुत से मजदूरों की जान ली गई और हत्या की गई. मालिकों मे अपनी वाच एण्ड वार्ड स्टाफ में समाज विरोधी और गुंडा तत्वों को भरकर उनका नये सिरे से गठन किया है और इन भाड़े के गुंडों के लिए मालिकों को बन्दूक के लाइसेन्स दिए गए हैं.

महाराष्ट्र, बिहार और केरल में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई और हड़तालों को तोड़ने के लिए दमनकारी कदम उठाये गये.

यहां तक कि एम. जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु बन्ध को तोड़ने के लिए 3000 मजदूरों और ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेताओं की बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कीं. अनेक राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों में अध्यादेश जारी कर के हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आपात कालीन शासन के सारे अनुभवों के बाद भी सम्बोधित राज्यों की जनता पार्टी की सरकारें इन कार्यवाहियों को उचित ठहरा रही हैं. मजदूर वर्ग को राज्य सरकारो के इस अशुभ रवैये को गंभीरता से लेना चाहिए.

यह सम्मेलन इस बात को भी नोट करता है कि समाज-विरोधी तत्व और भाड़े के गुंडे जो वास्तव में मालिकों के आदमी हैं, सीटू यूनियनों के मजदूरों पर हमले करते हैं और दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अन्तर्गत आने वाली यूनियनों के नाम में अपनी कार्यवाहियां करते हैं और मजदूर वर्ग की एकता और संगठित आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में ऐसा ही देखने में आया है. अभी हाल में बैंक कर्मचारियों के संघर्षों के दौरान जन हित की रक्षा के नाम में विभिन्न स्थानों पर इन तत्वों का इस्तेमाल बैंक कर्मचारियों पर हमला करने के लिए किया गया. यह सम्मेलन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से इस बात की अपील करता है कि वे इन गिरोहों को जो मूलतः मालिकों के लिए काम करते हैं मजदूर वर्ग की एकता और उनके संगठित आंदोलन के हित में अपना मानने से इंकार कर दें और उनकी कार्यवाहियों की भरपूर आलोचना करें.

सीटू का यह चौथा अधिवेशन पुलिस की गोलीबारी की और मालिकों के भाड़े के टट्टुओं और सरकार द्वारा मजदूरों और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर किए जाने वाले हमलों की जोरदार भर्त्सना करता है और भारतीय मजदूर वर्ग का

[शेष पृष्ठ 31 पर]

तमिलनाडु. . .

[पृष्ठ 17 से आगे]

के मजदूरों, राज्य परिवहन के मजदूरों और दूसरे केंद्रों और उद्योगों के दूसरे मजदूरों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सीटू के झंडे के नीचे जीवन और कार्य की हालत सुधारने और अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष चलाने पर बधाई देता है.

यह सम्मेलन तमिलनाडु सरकार की मजदूर विरोधी नीति की भर्त्सना करता है और इस बात की मांग करती है कि मजदूरों के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों को वापस लिया जाय, और ट्रेड यूनियन संघर्षों में पुलिस और प्रशासन की ओर से हस्तक्षेप न किया जाये.

सीटू का यह चौथा सम्मेलन सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति को और राज्य की सभी सीटू यूनियनों को इस बात के लिए बधाई देता है कि उन्होंने सरकारी शह पर प्रबंधकों द्वारा मजदूरों के विरुद्ध किए गए हमलों के विरुद्ध मजदूरों का संगठित संघर्ष चलाने के लिए अथक प्रयत्न किए और इन हमलों का मुकाबला करने में उन्होंने सफलता पाई और अनेक मामलों में खासी सुविधाएं हासिल की.

सीटू का यह चौथा सम्मेलन तमिलनाडु के मजदूर-वर्ग को बधाई देता है कि उसने अपने वर्ग की एकता को बुलंद करने के लिए शानदार प्रयत्न किए जो कि उनके अनेक संगठित संघर्षों से जाहिर होता है.

महिला कामगारों की मांगों पर

सीटू का यह चौथा सम्मेलन कामगार महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन के फैसलों का स्वागत करता है. अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकार किये गये बीस-सूत्री "कामगार महिलाओं के राष्ट्रीय मांगपत्र" का पूरा-पूरा समर्थन करता है.

भारत में कामगार महिलाओं की समस्याओं को मुद्दत से अनदेखा किया जाता रहा है. कामगार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून बनाये गये हैं, वे बहुत नाकाफी हैं. इन कानूनों में महिलाओं के पक्ष में जो व्यवस्थाएं हैं, मालिकान जान बूझकर उनका उल्लंघन करते हैं. इन कानूनों को लागू करने वाला सरकारी तंत्र निहायत प्रभावहीन है. बीड़ी, तंबाकू और बागानों तथा अन्य अनेक उद्योगों में समान वेतन कानून लागू ही नहीं किया गया. कामगार महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो प्रसवकाल में मिलनेवाली सुविधाओं से वंचित है. इसके अलावा कामगार महिलाओं के प्रति दुनिया भर का भेद-भाव बरता जाता है. बैंकों बीमा, व्यापारी दफ्तरों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के दफ्तरों में भी तरक्की और ऊंचे ओहदों पर नियुक्ति के मामले में उनके प्रति भेदभाव किया जाता है. कानूनों में व्यवस्था होने के बावजूद अन्य उद्योगों की तो बात ही क्या की जाय, सरकारी विभागों में भी कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेशे (पालनागृह) की सुविधा नहीं है. संगठित उद्योगों के क्षेत्र में भी कामगार महिलाओं के लिए अलग कमरों, भोजन घरों, गुसलखानों और और शौचालयों का प्रबंध नहीं है.

आजादी के बाद से मालिकान की लगातार यह नीति रही है कि कामगार महिलाओं की संख्या को बराबर घटाते रहा जाय. सूती कपड़ा और पटसन मिलों, कोयला खदानोंऔर अन्य अनेक उद्योगों में कामगार महिलाओं की घटी हुई संख्या को साफ देखा जा सकता है.

कामगार महिलाओं की समस्याओं पर भारत की ट्रेड यूनियनों ने भी अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है. ट्रेड यूनियनों और उनके नेतृत्व में महिला कामगारों की भागीदारी बेहद असंतोष-जनक है.

यह सम्मेलन ट्रेड यूनियनों का आह्वान करता है कि महिला कामगारों की समस्याओं पर उचित ध्यान देते हुए, ट्रेड यूनियन गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए कामगार महि-लाओं को बढ़ावा देते हुए और यूनियन के नेतृत्व में उन्हें जिम्मेदार पद देते हुए वे ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस कमजोरी पर काबू पायें.

भारत की कामगार महिलाओं के बीस-सूत्री राष्ट्रीय मांगपत्र में **ये मांगें शामिल हैं :**

रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाय. काम का दिन आठ घंटे का हो. कामगार महिलाओं को समान वेतन और सुअवसर प्रदान किये जायं. सभी कामगार महिलाओं को चार महीनों की सवेतन प्रसवकालीन छुट्टी दी जाय. यह सुविधा महिला खेत-मजदूरों को भी दी जाय और इस बीच प्रत्येक महिला को कम से कम पांच सौ रुपया तन स्वरूप दिया जाय. महिलाएं जहां भी काम करती हैं, वहां पालना घरों की व्यवस्था की जाय. कामगार महिलाओं की छंटनी पर पाबंदी लगायी जाय. न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय. संगठित उद्योगों में कामगार महिलाओं को प्रोविडेंट फंड तथा ग्रैच्युटी की सुविधा दी जाय. ऐसी सभी जगहों में, जहां महिलाएं काम करती हों, उनके लिए अलग शौचालयों, स्नानघरों और आराम के कमरों आदि की व्यवस्था की जाय. कामगार महिलाओं के विरुद्ध हर तरह का भेदभाव समाप्त किया जाय.

यह सम्मेलन कामगार महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन के इस फैसले का दिल खोलकर समर्थन करता है कि 30 मई 1979 को "कामगार महिलाओं के अखिल भारतीय मांग दिवस" के रूप में मनाया जाय और उनके बीस-सूत्री कार्यक्रम को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया जाय. सम्मेलन सीटू से संबद्ध सभी यूनियनों का आह्वान करता है कि वे इस कार्यक्रम में कारगर ढंग से भागीदारी करें और इसे शानदार तरीके से सफल बनायें.

यह संमेलन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनि-यनों और मजदूरों व कर्मचारियों के राष्ट्रीय फैडरेशनों से अपील करता है कि वे मिलकर कामगार महिलाओं के इस राष्ट्रीय मांगपत्र का पूरा-पूरा समर्थन करें और 30 मई 1979 को कामगार महि-लाओं के अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में मनायें. इससे हमारे देश में काम-गार महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक एकजुट कार्रवाइयों में मदद मिलेगी.

वियतनाम...

[पृष्ठ 16 से आगे]

प्रगतिशील और जनवादी ताकतें स्वागत कर रही हैं.

संमेलन को हार्दिक आशा है कि दोनों समाजवादी देशों के बीच बात-चीत शुरू होगी और उनके बीच जो समझौते पहले हो चुके हैं उन्हीं के अनुरूप सीमा विवादों का निपटारा कर लिया जायगा.

संमेलन जनवादी चीन के नेतृत्व से अपील करता है कि वियतनाम पर उनकी चढ़ाई से चीनी जनता के हितों और तमाम दुनिया के मजदूर वर्ग के आंदोलन का जो जबरदस्त नुकसान हुआ है, उसे महसूस करें. इसका एक नतीजा यह हुआ है कि भारत और चीन के संबंधों को सामान्य बनाने के काम में रुकावट डालने के लिए हमारे देश में चीन विरोधी लाबी सक्रिय हो उठी है. जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हुए वियतनाम और चीन के संबंधों को पंचशील और सर्वहारा एकजुटता के आधार पर सामान्य बनाने की जिम्मेदारी जनवादी चीन के नेतृत्व पर है.

सीटू के चौथे सम्मेलन में चुने गए जनरल काउंसिल के सदस्यों के नाम

उड़ीसा

कामरेड अजेया राउत, लक्ष्मीधर बिस्वाल, का. शिवाजी पटनायक.

असम

कामरेड अमल घोष दस्तीदार*, धनी राम खोसला, सुकुमार चक्रवर्ती और का. सर्वेश्वर दास.

दिल्ली

कामरेड जयंत राय*, शादी राम, एस. बी. भारद्वाज, मोहन लाल, बी. के. पालीवाल, जोगेन्द्र शर्मा और का. वीरेन्द्र सिंह सिरोही.

हरियाणा

कामरेड एस. एन. सोलंकी.

कर्नाटक

कामरेड एस. सूर्यनारायण राव*, सी. नाजुनदप्पा, टी. एस. मनी, पी. रामचन्द्र राव, ए. जानम्मा‡, महामेद दस्तागीर, वी. जी. के. नायर, के. मूसब्बा और का. एन. के. उपाध्याय.

महाराष्ट्र

कामरेड पी. के. कुरने*, मदन फडनिस, के. एल. बजाज, पी. आर. कृष्णन, यशवंत कोली, पी. पी. संजगिरी*, खोपकार, वी. जी. पदमानाभन, दिनकर कादव, बी. पी. कश्यप, अहिल्या रांगणेकर*‡, के.एल. मल्हाबादे, प्रभाकर मांकड़ और का. सीताराम मंजरेकर.

मध्य प्रदेश

कामरेड एस. कुमार*, मोती लाल शर्मा, एस. सुखदेवन, बंसीधर आजाद, एम. के. विजयन और का. एस. एस. भट्टाचार्य.

त्रिपुरा

कामरेड बिरेन दत्ता.

राजस्थान

कामरेड डी. डी. शिराली, कृष्णकांत वर्मा, महावीर सिंह हांडा, परमेंद्र नाथ ढांढा, हेतराम बेनीवाल और का. पूर्णानन्द व्यास.

बिहार

कामरेड टी. एन. सिंह, एस. के. बख्शी ए. के. राय, बी. के. सिंह, चंडी प्रसाद* और का. हरी कृष्ण.

उत्तर प्रदेश

कामरेड हरसयाय सिंह*, दौलत राम, के. एन. भट्ट, अलबेल सिंह और का. अरबिंद कुमार.

हिमाचल प्रदेश

एक सदस्य बाद में चुना जाएगा.

पश्चिम बंगाल

कामरेड कृष्णपद घोष*, बिमल चैटर्जी*, रबिन मुखर्जी*, राजदेव गोयला*, श्याम सुंदर मिश्रा*, शांति घटक*, गोपाल बोस*, जामिनी शाह*, तरुण सेन-गुप्त*, मोहम्मद अमीन*, राधिका बैनर्जी*, जीबन बिहारी रे*, बामापद मुखर्जी*, सुनील बसु रे*, हरीसधन मित्रा*, चित्ता-ब्रत मजूमदार*, परिमल मित्रा*, दिनेन भट्टाचार्य*, प्रबीर सेन*, बिरेन राय*, बिजाय पाल*, आनंद पाठक*, लक्ष्मी सेन, हरीदास मालाकार, जयगोपाल रे, असीम बैनर्जी, बादल कार, बिजय भट्टाचार्य, रघुनाथ कुसारी, निरंजन मुखर्जी, नारायण साहा, सुजीत दास, सुशील गांगुली, रबिन चक्रवर्ती, के. के. राय गांगुली, सुखमय पाल, बिजोन साहा, इन्द्रदेव माली, निर्मल रे, बिशेश्वर गांगुली, काली घोष, बिजाय चक्रवर्ती, रबिन मजूमदार, जयंत दासगुप्ता, तारित तोपदार, खिति बर्मन, चतुर अली, अजीत चौधरी, शिब प्रसाद भट्टाचार्य, जगदीश दास, मनीमोहन मंडल, अबुल बसेर, अजीत बोस, लक्ष्मण भट्टाचार्य, समिरन जदाब, शांति चैटर्जी, गोपाल बिसवास, सीताराम गुप्ता, चन्द्रा राय, सिराजुद्दीन मौला, नानी कार, बिरेन गुप्ता, अजीत मुखर्जी, दिलीप मजूमदार, अर्धेंधु दख्शी, स्वप्प बोस, बिनाय के. चक्रवर्ती, सुखेन सरकार, हाराधन राय, रबीन सेन, विकास चौधरी, रामपद बैनर्जी, लक्ष्मण बाग्दी, बबालेन्दु भट्टाचार्य, अजीत चक्रवर्ती, संतोष दत्ता, प्रोलय तालुकदार, पांचु बोस, कमल बख्शी, मनी दत्ता, बलराम अदक, मानिक चक्रवर्ती, शेख सुलतान, बादल बोस, बिरेन बोस, संगदोगाल लेप्चा, हर्का बहादुर राय, मानिक सान्याल, पुनई ओराओं, बिरसेन कुजूर, मोहनलाल ओराओं, बाबूलाल गोपे, शांति दास गुप्ता, रबी सिन्हा, दिलीप चैटर्जी, कमल भट्टाचार्य, मुहम्मद इस्राइल, सैलेन चैटजी, अजीत भौमिक, सनातोन मल्लिक, शांताश्री चैटर्जी, अदुल हसन, निरोद चक्रवर्ती, एम. ए. सयीदे, हर्षी बैनर्जी, गोपाल आचार्य, मदन दास, बिरेन चक्रवर्ती, दीप नारायण सिंह, सिसिर बैनर्जी, सुनोल रजंन घोष, सुबास बोष, सुबोध गांगुली, राम शंकर प्रसाद, सुनील दास, जेठीमाया रैनी,‡ शिबानी सेनगुप्ता‡, पी. गंगाम्मा‡, और का. मधुगुहा.

तमिलनाडु

कामरेड ए.बाला सुब्रामन्यम*, आर. उमानाथ*, ए. नल्लाशिवन*, वी. पी. चितन*, के. एम. हरीभट्ट, डी. जानकी रमन, पी. जी. के. कृष्णन, सी. गोविंदराजन*, एस. वीराभद्रन, पी. रामचन्द्रन, एम. नंजप्पन, टी. बालन, वी. कर्मेगम*, एस. ए. थागंराजन, पी. सोरानम, जे. हेमचन्द्रन, बी. कन्नन, वी. रामासामी, के. अनन्दन नांबियार, टी. के रंगाराजन, एस. ए. पीरूमल, और एक स्थान बाद में भरा जाएगा.

केरल

कामरेड ओ. भरथन*, के. पद्मानाभन,* एम. वसु,* सी. ओ. पाउलेजे*, के. एन. रविन्द्रनाथ*, वी. विश्व नाथ मेनन*, एम. एम. लोरांजे*, के. ओ. हबीब,* सी. बी. सी. वारियर*, एन. पद्मालोचनन*, ओ. जे. जोसेफ*, अनथलवथ्थम अनंदन*, सी. पी. करूणा-करण पिल्लै,* एम. जिनादेवन*, पी. विजयन, ई. एस. रघुवरन, के. पी. सहादेवन, पी. वी. बालागोपालन, ए. के. नारायनन, के. मूसाकुट्टी, के. पद्मानाभन, ई. के. इंबिची बावा, के. सैंदलीकुट्टी, के.

[शेष पृष्ठ 33 पर]

मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों की कटु आलोचना

[पृष्ठ 14 से आगे]

में डाल रहा है और किस प्रकार पूंजीवादी इसका फायदा उठाकर मजदूर वर्ग में विभाजन कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर सीटू सही नीति अपनाए जिससे समस्त मजदूर वर्ग को एकजुट किया जा सके तथा पूंजीवादियों के इस रवैये का भारी हार दी जा सके.

कई डेलीगेटों ने अपने भाषणों में जनता सरकार की मजदूर वर्ग के खिलाफ नीतियों की आलोचना की और इन नीतियों के खिलाफ किए गए संघर्षों के बारे में बताया. उन्होंने सीटू की अगुवा भूमिका का तथा वेतनजाम, औद्योगिक संबंध विधेयक और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित एकजुट आंदोलनों की भी चर्चा की.

बहस के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सीटू को उद्योगानुसार आंदोलन के निर्माण में अधिक दिलचस्पी लेने की जरूरत है ताकि बुर्जुआ नीतियों के खिलाफ एक मजबूत विरोध को ठीक प्रकार से संगठित किया जा सके. उन्होंने महिला श्रमिकों की समस्याओं के बारे में आंदोलन शुरू करने तथा महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूरों के एकजुट संघर्षों को आयोजित करने का भी जिक्र किया. पश्चिम बंगाल में अपनी परीक्षा की घड़ी में किए गए बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता कार्य के बारे में भी वक्ताओं ने रिपोर्ट दी. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ, जिनकी भूमिका पिछले दिनों बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, संघर्ष करने की जरूरत पर भी वक्ताओं ने जोर दिया. उन्होंने 'भेल' द्वारा हाल ही में सीमेंस के साथ किए गए समझौते की ओर संकेत किया और सरकार द्वारा इसी तरह के दूसरे समझौतों का पर्दाफाश करने की जरूरत को बताया. पश्चिम बंगाल के कई वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार सीटू ने अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर हड़ताली संघर्ष किए और किस तरह वाममोर्चा सरकार के सहायतापूर्ण रवैये के साथ मजदूर वर्ग मालिकान से कई तरह की सुविधाएं पाने में सफल हुए.

सीटू उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया और बिजली की कमी, फैक्ट्रियों की बंदी और पूरी कैपेसिटी से न चलने के कारण बेरोजगारी की वजह से राज्य के सामने पैदा हुई कई दिक्कतों की ओर इशारा किया. उन्होंने राज्य सरकारों के लिए अधिक आर्थिक शक्ति देने की मांग की ताकि आर्थिक कठिनाइयों को कुछ हद तक हल किया जा सके.

कामरेड राममूर्ति ने बहस का उत्तर देते हुए वक्ताओं द्वारा सुधार के लिए पेश किए गए कुछ सुझावों को स्वीकार किया और बहस के दौरान उठाए गए कुछ सवालों की सफाई पेश की. उन्होंने सीटू की गतिविधियों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन में सीटू एक जबरदस्त ताकत बने.

जनरल कंफेडरेशन आफ रोमनियन ट्रेड यूनियंस की ओर से कामरेड स्तान जार्जी ने बधाई संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि सीटू और रोमानियन ट्रेड यूनियनों में बिरादराना संबंध और मजबूत होंगे. वियतनामी दूतावास के प्रथम सचिव कामरेड हाजुय ने वियतनाम फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस की ओर से सम्मेलन को बधाई दी. उन्होंने वियतनाम के ट्रेड यूनियन आंदोलन की गतिविधियों की समीक्षा की तथा बताया कि वियतनाम के मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व देश की क्षेत्रीय रक्षा में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

कामरेड एम. के. पंधे ने सीटू संविधान में संबद्धता फीस 10 पैसे प्रति सदस्य

[शेष पृष्ठ 24 पर]

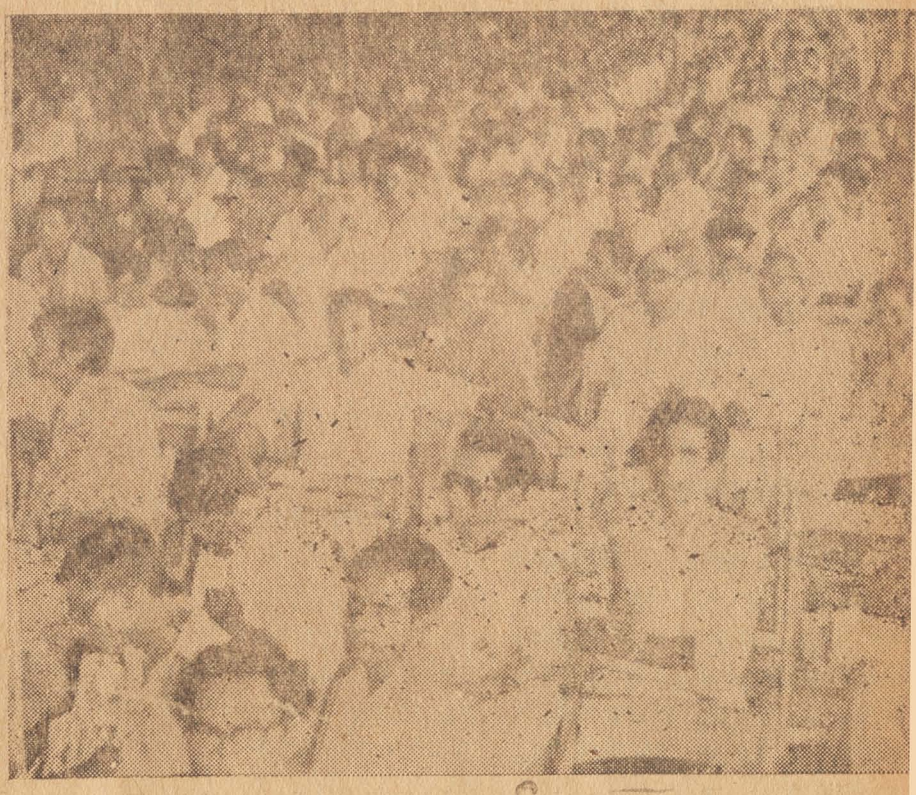

सम्मेलन का एक दृश्य

सीटू सम्मेलन ने मजदूर वर्ग में जबरदस्त उत्साह पैदा किया

[पृष्ठ 23 से आगे]

से 20 पैसे करने का और सीटू सम्मेलन में डेलीगेशन भेजने की बाबत संशोधन पेश किए. सम्मेलन ने संशोधनों को स्वीकार कर लिया और सीटू सम्मेलन मे भेजे जाने वाले डेलीगेशन के सदस्यों की संख्या डेलीगेटों की कुल संख्या व छोटी यूनियनों के हितों को मध्यनजर रखते हुए जनरल कांउसिल तय करेगी.

कोषाध्यक्ष, कामरेड मनोरंजन राय ने 1975 से 1978 तक का लेखा पेश किया. जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया. कामरेड ए. नानाशिवम् ने क्रेडेंशल कमेटी की रिपोट पेश की जिसमें बताया गया कि 1,473 यूनियनों ने जिसकी सदस्यता 11,48,966 है, ने सम्मेलन में भाग लिया है. रिपोर्ट मे कहा गया है कि नवबर 1978 की जनरल काउंसिल की बैठक तक सीटू के साथ 2,934 यूनियनें सबद्ध थी. बहुत सी यूनियनें संघषरत होने, फैक्ट्रयों म तालाबदी और जबरदस्त आर्थिक दिक्कतों के कारण सम्मेलन में भाग नहीं ले सकीं. लेकिन उन्होंने राज्य सम्मेलनों में भाग लिया था. यदि राज्य सम्मेलनों में भाग लेने वाली यूनियनों की सदस्यता को मध्येनजर रखा जाए तो 1978 में सीटू की सदस्यता 15 लाख भी ज्यादा थी.

कमेटी ने नई यूनियनों के 580 संबद्धता फार्मों की जांच पड़ताल की, 291 यूनियनों ने सबद्धता की सभी जरूरतों को पूरा किया था और बाकी से एक महीने के अंदर और जानकारी देने के लिए कहा गया है. क्रेडेंशल कमेटी की रिपोर्ट सर्वसम्मति से पास हुई.

सम्मेलन ने मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं पर कई प्रस्ताव अपनाए. इनमें बोनस, गुप्त मतदान से यूनियनों की मान्यता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार, सार्वजनिक उद्योगों में वेतन समझौतावार्ताओं, बेरोजगारी, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता, मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्यवाहियों, वियतनाम, राज्य सरकार कर्मचारियों के संघर्षों, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारों की उपलब्धियों, महिला श्रमिकों की मांगों, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, बागान मजदूरों की मांगों, दवा उद्योग में विकिट-माइजेशन और तमिलनाडु के मजदूरों को बधाई पर प्रस्ताव पास किए. सम्मेलन ने 1979 के लिए मई दिवस का घोषणा पत्र भी अपनाया. प्रस्ताव कमेटी को विभिन्न उद्योगानुसार मांगों व मजदूर वर्ग की दूसरी समस्याओं पर प्रस्ताव दिए गए. सम्मेलन ने सेक्रेट्रीयल को इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और सब में बांटने का कार्य सौंपा.

कामरेड बी. टी. रणदिवे ने सम्मेलन की उपलब्धियों की समीक्षा की और संगठन की कमजोरियों को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि सीटू और अच्छी तरह से मजदूर वर्ग को कामन मांगों पर संगठित करने मे जबरदस्त भूमिका निभा सके. उन्होंने महिला श्रमिकों की समस्याओं पर जिसके बारे में अतीत में कुछ भी नहीं किया गया विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया.

मद्रास के मुख्य मांगों से 6 मील की दूरी तय करते हुए एक विशाल रंगीन जुलूस निकाला गया. प्रदर्शनकारी विभिन्न भाषाओं में लिखे गए झंडे और फैस्टून लिये थे जो सभी राज्यों के मजदूर वर्ग की एकता दर्शा रहे थे. हर जगह हजारों हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जुलूस का स्वागत कर रहे थे.

ट्रिप्लीकेन बीच पर जुलूस एक विशाल रेली में बदल गया जिसकी कामरेड ए. बालासुब्रामन्यम ने अध्यक्षता की. इस सभा को कामरेड बी. टी. रणदिवे, ज्योति बसु, पी. राममूर्ति, वी. पी. चिंतन, अहिल्या रांगणेकर, आर. ऊमानाथ, और एम. के. पंधे ने संबोधित किया. रोमानिया की ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग की ओर से रोमानियन डेलीगेट स्तान जार्जी ने सभा को मुबारकबाद दी.

सम्मेलन ने समूचे देश के डेलीगेटों और तमिलनाडु के मजदूर वर्ग में जबरदस्त उत्साह पैदा किया.

सम्मेलन के सभी प्रबंधों को सुचारू रूप से करने में स्वागत समिति की एक जबरदस्त वालिंटियर दस्ते ने सहायता की. सीटू यूनियनों के अतिरिक्त एल. आई. सी., बैंक, कमर्शल संस्थानों और अन्य उद्योगों के कर्मचारियों ने सम्मेलन की जबरदस्त सफलता के लिए दिन रात काम किया.

सीटू के नए प्रकाशन

'दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास'

(अंग्रेजी में)

सीटू के चौथे सम्मेलन की समीक्षा, सम्मेलन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव

मूल्य : तीन रुपये

सम्मेलन के अन्य प्रकाशन

(अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध)

अध्क्षीय भाषण

--बी. टी. रणदिवे

मूल्य : 1.00 रुपया

महासचिव की जनरल रिपोर्ट

--पी. राममूर्ति

मूल्य : 75 पैसे

कार्य और संगठन की रिपोर्ट

--एम. के. पंधे

मूल्य : 1.00 रुपया

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

सीटू के चौथे सम्मेलन को बिरादराना संदेश

कामरेड देवकुमार गांगुली, महासचिव, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बुडापेस्ट, (डब्ल्यू. एफ. टी. यू.)

सभी महाद्वीपों के देशों के एक करोड़ 75 लाख सदस्यों की ओर से सीटू के चौथे सम्मेलन के सभी डेलीगटों को बिरादराना शुभकामनाएं दे रहे हैं. आपको सम्मेलन की कार्यवाही और एकता तथा भारत के मजदूर वर्ग की संयुक्त कार्यवाहियों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए कार्य निर्धारण, ताकि काम और निर्वाह की हालतों में सुधार और ट्रेड यूनियन अधिकारों व हड़ताल के अधिकार सहित जनवादी स्वतंत्रता के लिए खास तौर से ट्रांसपोर्ट में संघर्ष को और मजबूत बनाया जा सके, के लिए हर सफलता की कामना करते हैं. भारतीय मजदूर वर्ग के जबरदस्त साम्राज्यवाद विरोधी रूझान की सत्यता को मानते हुए हमारा विश्वास है कि आपका सम्मेलन शांति और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्षों को और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ एकजुटता को और मजबूत बनाने में सहायक होगा.

———

कामरेड माकीदा, अध्यक्ष, सोहयो, जापान

प्रिय अध्यक्ष और डेलीगेटों, सीटू के चौथे सम्मेलन के अवसर पर हम आपको हार्दिक बधाई और बिरादराना शुभ कामनाएं देते हैं. अतीत में आपने जो जबरदस्त सफलताएं प्राप्त की हैं उन्हें हम भली-भांति जानते हैं और हमें विश्वास है कि इस सम्मेलन के बाद आपके भावी संघर्ष और अधिक फलदायक होंगे. हम आशा करते हैं कि हमारे दोनों संगठनों के बीच और दोनों देशों के मजदूरों के बीच कर्मठ एकजुटता और अधिक मजबूत होगी. आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करते हैं.

———

कामरेड अल्डो बोक्सिनी, सी. जी. आई. एल., अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सचिव, इटली

सीटू के चौथे सम्मेलन, 11 से 15 अप्रैल, में सी. जी. आई. एल. को डेलीगेशन भेजने के लिए निमंत्रण के लिए शुक्रगुजार हैं. यहां मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण हम संघर्षों में व्यस्त हैं इसलिए दुर्भाग्यवश हम इस निमत्रंण को स्वीकार नहीं कर सकते. भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता और उसकी सफलता में महत्वपूर्ण प्रगति में हमारी गहरी दिलचस्पी और संतुष्टी है. भारतीय मजदूरों को और खास तौर से आपके केन्द्र की ट्रेड यूनियन अधिकारों और मजदूर वर्ग की निर्वाह की हालतों की रक्षा करनी हैं. आपके सम्मेलन के डेलीगेटों के शुभकार्य और भारतीय व दूसरे देशों के मजदूरों की शांति और जनता की स्वतंत्रता के लिए संघर्षों में सफलता की कामना करते हैं. बिरादराना शुभकामनाएं.

——

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ कामर्स एम्प्लाईज, प्राग, चेकोस्लोवाकिया

चौथे सम्मेलन को बधाई. सफलता की कामना करते करते हैं. भारत में ट्रेड यूनियन और जनयादी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षों के साथ संयुक्त कार्यवाहियों द्वारा एकजुटता व्यक्त करते हैं.

———

कामरेड एन्रोक्यू पास्टोरिनी, महासचिव, डब्ल्यू. एफ. टी. यू.

सीटू के चौथे सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं. इन्हीं तारीखों में डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की जनरल कांउसिल की बैठक के होने की वजह से हम अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज पा रहे हैं इसके लिए हमें खेद है. डब्ल्यू. एफ. टी. यू. सम्मेलन और नई दिल्ली में पिछली नवंबर में आयोजित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन को मजदूरों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझती है.

——

मास्को, सोवियत संघ

सोवियत श्रमिक जनता की ओर से आल यूनियन सेंट्रल कांउसिल आफ ट्रेड यूनियंस सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के चौथे सम्मेलन के डेलीगेटों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजती हैं. हम भारतीय श्रमिक जनता के आपके देश में अपने महत्वपूर्ण हितों और जनवादी अधिकारों को, मजदूरों व ट्रेड यूनियन आदोलन की शांति, जनवाद और सामाजिक प्रगति के लिए एकता हासिल करने के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संघर्षों की सफलता की कामना करते हैं.

(पृष्ठ 36 भी देखें)

गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों की शक्ति परखी जाए

[पृष्ठ 12 से आगे]

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स और इससे संबंधित कुछ विभागीय ट्रेड यूनियन इन्टरनेशनल शामिल हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन : बंबई सम्मेलन के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन [आई. एल. ओ.] से सीटू के संबंध और मजबूत हुए हैं. सीटू ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित ज्ञापन भी आई. एल. ओ. को भेजे हैं. आई. एल. ओ. ने कुछ गोष्ठियों में भी सीटू को आमंत्रित किया. इसके कई प्रतिनिधि सीटू दफ्तर आए व सीटू प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया.

नई यूनियनें : वर्किंग कमेटी और जनरल कांउसिल ने बंबई सम्मेलन के बाद 490 यूनियनों को अपने साथ संबंधित करने की मान्यता दी है. इसका ब्यौरा देते हुए कामरेड पंधे ने कहा "यद्यपि यह एक शुभ लक्षण है कि अधिक से अधिक यूनियनें सीटू के साथ जुड़ रही हैं और इसके अनुशासन में काम कर रही हैं, फिर भी ऐसे कदम उठाना जरूरी है जिनसे हमें भरोसा रहे कि ये यूनियनें सीटू की जरूरतों का वक्त से पालन करती रहें."

सीटू के साथ भेदभाव : केन्द्रीय सरकार सरकारी कमेटियों में विभिन्न ट्रेड यूनियनों को 1968 की सदस्यता की जांच पड़ताल के आधार पर नामजदगी देती आ रही है. इसका विरोध करते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "यह सभी को मालूम है कि 1968 में सीटू बनी ही नहीं थी. इस आधार पर उसके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है."

कोई कदम नहीं : कामरेड पंधे ने फिर बताया कि "हमने कई मौकों पर केन्द्रीय श्रम मंत्री के सामने इस समस्या को रखा है. 1970 में प्रारंभिक जांच-पड़ताल के लिए हमने एक सूची दी मगर हमारी सदस्यता के मामले पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. 1972 में फिर से हमने जांच के लिए एक और सूची दी, मगर राजनीतिक कारणों से उसकी सत्यता की भी जांच सरकार ने नहीं कराई."

गुप्त मतदान : उन्होंने कहा कि "1978 में भारत सरकार ने सीटू से फिर से सूची पेश करने को कहा. सीटू ने सरकार को लिखा कि सदस्यता की जांच की पद्धति का हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि गुप्त मतदान द्वारा हमारी यूनियन की शक्ति को परखा जाय. सीटू ने इस सवाल पर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग की भी मांग की."

समर्थन : रिपोर्ट में कामरेड पंधे ने आगे बताया कि "सरकार ने इस मामले पर बातचीत करने के लिए अगस्त 1978 में एक मीटिंग बुलाई. सीटू ने गुप्त मतदान के सुझाव पर दबाव डाला और लगभग सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यह तय हुआ कि इस मसले पर विचार करने के लिए एक छोटी-सी कमेटी बना दी जाए. इस कमेटी की मीटिंग 4 अक्तूबर, 1978 को हुई. इसमें सीटू व एच. एम. एस. के नुमाइन्दों ने गुप्त मतदान पर जोर दिया, बी. एम. एस. ने गुप्त मतदान का समर्थन किया मगर कहा कि अगर इसमें देर होने की आशंका हो तो जांच-पड़ताल वाली पद्धति ही रखी जाए. इन्टक और एटक के नुमाइन्दों ने जांच-पड़ताल वाली पद्धति का समर्थन किया. सीटू ने एटक के इस फैसले की खुलकर आलोचना की तब कहीं एटक के नेताओं ने गुप्त मतदान के समर्थन में बयान दिया."

मामला ठप्प : सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि "अभी भी सारा मामला ठप्प पड़ा है और सरकार का गुप्त मतदान कराने का कोई इरादा नहीं है. सरकार अभी भी उन्हीं पुराने अस्थायी निर्णयों के आधार पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को नामजदगी देती आ रही है, जाहिर है कि सीटू के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव बरता जा रहा है."

श्रमिक महिला सम्मेलन : 1978 में कोटा में हुई वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक, सीटू ने अखिल भारतीय महिला मजदूरों की कन्वेन्शन करने के लिए तैयारी-कमेटी बनायी थी. राज्य कमेटियों के सुझावों के आधार पर कुछ और महिला सदस्यों को कमेटी में शामिल कर लिया गया था. इस तैयारी-कमेटी की कंवेशंन की तैयारियों के बारे में बताते हुए और विभिन्न राज्यों में हुए श्रमिक महिला सम्मेलनों में हुई बहस पर प्रकाश डालते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "आमतौर पर ट्रेड यूनियन आंदोलन ने महिला मजदूरों की समस्याओं के प्रति एकदम उपेक्षा का रवैया जो अख्तियार किया हुआ है उसको भी उन्होंने उजागर कर दिया. अतः यह जरूरी है कि सीटू यूनियनें महिला मजदूरों की समस्याओं को अपने हाथ में लें और यूनियन के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें."

सीटू के अखबार : सीटू के अंग्रेजी मासिक 'दि वर्किंग क्लास' की चर्चा करते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "राज्य कमेटियां अपने यहां हुए संघर्षों और सामूहिक आंदोलनों की समीक्षा-रपट सही तरीके से तैयार नहीं करतीं. इससे संघर्षों के दौरान प्राप्त स्थानीय अच्छे अनुभवों का फायदा अपने झंडे के नीचे संघर्षरत यूनियनों को हम ठीक तरह नहीं पहुंचा पाते. कभी-कभी अकेली यूनियनें अपनी रपट इतनी देर से भेजती हैं कि छपने के वक्त तक उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है."

इसके अतिरिक्त 'सीटू मजदूर' [केंद्रीय हिंदी मासिक], 'श्रमिक आंदोलन' [बंगाल], 'सीटू संदेशम्' [केरल, मलयाली], 'कार्मिक लोकम्' [आंध्र प्रदेश, तेलुगु] और 'वर्गयुद्ध' [महाराष्ट्र, मराठी] की चर्चा करते हुए हुए उन्होंने

[शेष पृष्ठ 30 पर]

समान अधिकारों के लिए एकजुट संघर्ष जरूरी

श्रमिक महिला सम्मेलन का आह्वान

प्रथम श्रमिक महिला संमेलन सी. आई. टी. यू. के आयोजन में 9-10 अप्रैल को मद्रास में हुआ. सोलह राज्यों से 440 महिला प्रतिनिधियों ने संमेलन में भाग लिया. संमेलन के संचालन के लिये एक अध्यक्ष-मंडल चुना गया जिसकी का. अहिल्या रांगणेकर, सुशीला गोपालन, डा. लक्ष्मी सहगल, शिवानी सेनगुप्त, मणिक्कम, कोवरी अम्मा, तथा सम्मुगम सदस्य थीं.

स्वागत समिति की ओर से का. मैथली शिवरामन ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

संवैधानिकों अधिकारों से वंचित

कामरेड बी. टी. रणदिवे ने संमेलन का उद्घाटन करते हुये व श्रमिक महिला संमेलन बुलाने की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अनेक अधिकार दिये गये हैं. पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं हैं. लेकिन फिर भी महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है. महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती है फिर भी उन्हें पुरुषों से कम तनखाह दी जाती है. उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण बढ़ता ही जा रहा है.

महिला प्रधान मंत्री

उन्होंने भूतपूर्व महिला प्रधान मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि महिला होते हुए भी उन्होंने श्रमिक महिलाओं के हालात में कोई सुधार नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसी महिला प्रधान मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी की घोषणा करके तानाशाही लागू की, और अनेक महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक कष्ट सहने पड़े. इन्हीं के शासन में महिलाओं को कम दहेज मिलने के कारण जबरदस्ती जलाया जाता रहा.

सीटू की पहल कदमी

गरीबों और महिलाओं के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया. महिला प्रधान मंत्री के शासन में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार नहीं मिले. उन्होंने कहा कि समान अधिकार पाने के लिए महिलाओं को जबरदस्त लड़ाई लड़नी होगी और इस बारे में यह संमेलन बुला कर सी. आई. टी. यू. ने पहल कदमी की है.

कागजी कानून

का. रणदिवे ने आगे कहा कि 1976 में बने समान काम के लिए समान वेतन के कानून के बावजूद आज भी चाय बागान, नारियल, बीड़ी, सुत व अन्य उद्योगों में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है. और यह कानून भी एक कागजी कानून ही बनकर रह गया है.

शादी या नौकरी

सीटू के अध्यक्ष ने बताया कि दूसरे देशों में भारतीय महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी. जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भी प्रसूति भत्ता देने और महिलाओं को भारी बोझ और रात्रि-कार्य देने पर रोक लगाने के कानून पास किए. आजादी के बाद भारत सरकार ने भी कई कानून पास किये लेकिन 32 साल के बाद भी सब कानून कागजी ही रहे. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिक महिला को समान वेतन और प्रसूति भत्ता न देने पर एक भी पूंजीपति को आज तक सजा नहीं हुई और अदालत और सरकार भी मामूली दंड देने के सिवाए कुछ नहीं कर सकी. इतना ही नहीं प्रसूति भत्ता देने से छुटकारा पाने के लिए मालिक महिला कामगारों को शादी के बाद काम से निकाल देते हैं.

जबरदस्त भेदभाव

सरकार की आलोचना करते हुए कामरेड रणदिवे ने बताया कि महिला श्रमिकों द्वारा अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए निजी ही क्या सरकारी दफ्तरों में भी बाल भवन नहीं हैं. उनके लिए दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्हें अपनी तरक्की और तबादले के लिए भी परेशान होना पड़ता है. नौकरी देते वक्त भी भेदभाव किया जाता है. स्वास्थ्य और टेलीफोन केन्द्रों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है. जनता पार्टी के 10 साल में बेरोजगारी समाप्त करने का चुनाव-वायदों के बावजूद बेरोजगारी पहले से अधिक बढ़ती गई और इसकी शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं. बावेजा कमेटी ने कोयला खादान में 50 हजार मजदूरों को काम से हटा देने का सुझाव दिया है. इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं.

खास नुमाइंदगी नहीं

ट्रेड यूनियनों में भी श्रमिक महिलाओं की कोई खास नुमाइंदगी नहीं है. और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भी इसकी कोई चिंता नहीं की है. इसकी चर्चा करते हुए कामरेड रणदिवे ने कहा कि महिलाओं को यूनियनों के कामों में हिस्सा लेना चाहिए और ट्रेड यूनियन आंदोलन को महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए.

मांग-दिवस

महिला सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि सी. आई. टी. यू. अन्य यूनियनों को साथ लेकर श्रमिक महिला सम्मेलन ने जो 20 सूत्री मांग-पत्र तैयार किया है उसके लिए देशभर में 30 मई को समान अधिकार और समान वेतन दिन मनाएगी. सी. आई. टी. यू. चाहती है कि महिलाएं भी अधिक संख्या में ट्रेड

[शेष पृष्ठ 28 पर]

आजादी के 32 साल बाद भी महिला श्रमिकों की हालत में सुधार नहीं

[पृष्ठ 27 से आगे]

यूनियनों में शामिल होकर और जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करें.

महिला श्रमिकों की संख्या घटी

कामरेड अहिल्या रांगणेकर ने अपने भाषण में कहा कि 1911 में महिला श्रमिकों की संख्या 31 प्रतिशत थी. यह संख्या घटकर 1974 में 11 प्रतिशत हो गई. सूती उद्योग में 50 हजार महिलाएं काम करती थी लेकिन आज सिर्फ 5000 महिलाएं हैं. उन्होंने बताया कि इंडियन एयर लाइंस की परिचारिका को पहले शादी करना मना था. काफी संघर्ष के बाद उन्हें शादी करने का अधिकार मिला लेकिन उन्हें बच्चा होने पर निकाल दिया जाता है. इसके अलावा 35 वर्ष की आयु के बाद उन्हें काम से हटा दिया जाता है.

महिलाओं को हीन समझना

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कामरेड विमला रणदिवे ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में श्रमजीवी महिलाओं की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के बाद भी श्रमिक महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया. इसका कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सरकार, पूंजीपतियों व जमींदारों द्वारा महिलाओं का हीन समझना तथा उनका शोषण करना आदि बताते हुए का. विमला रणदिवे ने कहा कि भारतीय ट्रेड यूनियनों ने भी श्रमजीवी महिलाओं की स्थिति पर पूरा ध्यान नहीं दिया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1974 में संगठित क्षेत्र में 21,88,000 महिलाओं में से सिर्फ 2,62,000 श्रमजीवी महिलाएं ट्रेड यूनियन की सदस्य थीं. यह ट्रेड यूनियन की काफी बड़ी कमजोरी है. यही कारण है कि मालिक महिलाओं का अधिक शोषण करने में सफल रहे. उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिये पुरुषों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए.

मांग पत्र

कामरेड विमला रणदिवे ने इस रिपोर्ट के साथ देश की श्रमिक महिलाओं की हालत सुधारने के लिये एक 20 सूत्री मांग पत्र पेश किया. इस मांग पत्र में सभी ग्रामीण व महिला कामगारों के प्रसूति के लिये पूरे वेतन व चिकित्सा सुविधाओं सहित चार महीनों की छुट्टी, समान काम के लिये समान वेतन, शिशु गृह, महिला श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा देने, शादी के बाद महिला कामगार को नौकरी से निकालने पर रोक, सुरक्षा, सभी प्रकार का शोषण खत्म करने आदि की मांगें शामिल हैं.

देश व्यापी आंदोलन की अपील

यह मांग-पत्र पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों को पाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों तथा महिला संगठनों के अपील की कि वे श्रमिक महिलाओं की जिंदगी को सुगम बनाने व सभी क्षेत्रों में समान स्थान दिलाने के लिये देश व्यापी आंदोलन छेड़ें.

मां बनना एक जुर्म

10 अप्रैल को कामरेड सुशीला गोपालन ने कहा कि हमें सिर्फ श्रमजीवी महिला आंदोलन नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन और जनवादी आंदोलन को भी मजबूत करना है. पूंजीवादी व्यवस्था के घोर अमानवीयपन का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मां बनना आज एक जुर्म बन गया है. अपने अधिकारों को हासिल करने लिए केवल मांग करने से कुछ नहीं होगा बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ एक लम्बी लड़ाई लड़नी होगी.

प्रतिनिधित्व

कुल 45 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट तथा मांग-पत्र पर बहस की. उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव भी बताये. विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधियों ने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया. अनुवाद की सुविधा होने के कारण बहस में लगातार रूची बनी रही और सभी सम्मेलन की कार्यवाही समझ पाए. इनमें काजू, कैयर, चाय, प्राध्यापक, डाक्टर, बैंक, बीमा आदि उद्योगों के प्रतिनिधित्व करने वाली महिलायें थी.

रुमानिया में समानता

रुमानिया के शिष्ट मंडल के नेता कामरेड स्तान जार्जी और हेंटर गावरीला तथा कामरेड झामा, सचिव इंडो-रुमानिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने सम्मेलन का अभिवादन किया. उन्होंने बताया कि रुमानिया में समाजवाद आने के बाद महिलाओं को हर स्तर पर समानता का दर्जा प्राप्त हुआ है और 32 प्रतिशत महिलाए काम कर रही है.

विरोध में प्रस्ताव

बंबई की डा. सुजाता ढवले ने ईरान की बहादुर महिलाओं का अभिनंदन करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इन्होंने अमरीकी कठपुतले ईरान के शाह को खदेड़ने में और नये शासकों द्वारा जारी औरतों पर बुर्का लादने की प्रतिगामी कदम के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी. उत्तर प्रदेश में बस्ती इलाके में बड़े पैमाने पर नर्सों के बलात्कार और केरल व बिहार में हरिजन महिलाओं पर बहशियाना जुल्म की घटनाओं की निंदा करते हुए और केंद्रीय बजट के विरोध में प्रस्ताव पास हुए.

इस सम्मेलन में 16 राज्यों से भाग लेने वाली 440 प्रतिनिधियों में से 81 जेल काट चुकी थीं. सबसे कम उमर, 18 साल, की प्रतिनिधि तमिलनाडु और सबसे ज्यादा उमर, 65 साल, की दिल्ली से आई थीं. 175 मजदूर वर्ग की, 162 मध्यम वर्ग तथा 32 ट्रेड यूनियन और महिला संगठनों की प्रतिनिधि थी.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

सीटू जुल्म की आग से तपकर निकली है

[पृष्ठ 10 से आगे]

कंपनियों के घुसपैठ की वकालत कर रही है." उन्होंने मजदूर वर्ग को ऐसे खिलाफ सावधान रहने का आह्वान किया जिनके अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां 60 लाख टन की क्षमता वाले इस्पात के कारखाने लगाती जिनमें दो या तीन हजार मजदूर काम करते. इसके अलावा अल्युमिनियम कारखाना लगाने का भी सुझाव था. और यहां तक कि बोकारो इस्पात कारखाने में भी उन्होंने बताया कि "इसके अलावा कुछ और सुझाव थे जिनके अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर कारखाने लगाने तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को खुद ही निर्यात करने की सुविधा थी."

परवाह : विदेशी पूंजी के प्रति सरकार की नीति की तीखी आलोचना करते हुए कामरेड पी. राममूर्ति ने कहा कि "हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी जनता पर पहले से ही अत्याचार कर रही है. वे न तो जनवादी ट्रेड यूनियन अधिकारों को मानती है और न सरकार के आदेशों या जनमत की ही परवाह करती है."

पानी फेरना : जनता सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स आयोग का पुनर्गठन किया है जिसके अध्यक्ष स्वदेशी बिजली उद्योग के विकास के पक्ष में रहने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इस क्षेत्र में घुसपैठ का विरोध करने के लिए मशहूर थे. इसका हवाला देते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "इलेक्ट्रोनिक्स आयोग के पुनर्गठन का उद्देश्य इस आयोग द्वारा दिए गए उन निर्देशों पर पानी फेरना है जिनके द्वारा इस क्षेत्र में नये लाइसेंसों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने से रोका जा सकता था."

स्तर्क : उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रसायन खाद के उत्पादन के लिए वनस्पतियों के आयात के खतरनाक प्रस्ताव के खिलाफ स्तर्क रहने का आह्वान किया.

तरजीह : कामरेड राममूर्ति ने बताया कि "एक और खतरनाक रुझान यह है कि समाजवादी देशों से हमारे आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के बजाय इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंध बनाने की तरजीह दी जा रही है."

मांग : ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारी सीटू की यूनियनें, राज्य कमेटियां व संस्थाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खतरों की ओर पूरा ध्यान दे पाई हैं. इसकी ओर इशारा करते हुए कामरेड राममूर्ति ने आह्वान किया कि "हमें एक स्वर से मांग करनी चाहिए कि सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्यौता देने व फायदे पहुंचाने वाली नीतियों से बाज आए."

भूमिका : पिछले कुछ समय में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने कई हड़ताल तथा आंदोलन चलाए हैं. ये आंदोलन न केवल रोज-ब-रोज की आर्थिक मांगों पर हुए हैं बल्कि उन सरकारी नीतियों के खिलाफ भी हैं जिनका सीधा प्रभाव मजदूर वर्ग पर हुआ है. इसका खुलासा पेश करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "अब समय आ गया है जबकि विभिन्न ट्रेड यूनियन आंदोलनों को वैकल्पिक आर्थिक व जनवादी नीतियों के लिए मिलकर संघर्ष करना है. इस क्षेत्र में सीटू को विशेष भूमिका अदा करनी है. इसे बार-बार मजदूर वर्ग के सामने भूमि संबंधी बुनियादी सुधार, एकाधिकारी घरानों व विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण, विदेशी कर्ज पर रोक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग की नीति के विरुद्ध संघर्ष तथा स्वदेशी तकनीक व वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास की नीतियों का समर्थन जैसे मुद्दे रखने चाहिए. हमें यह साफ समझ लेना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ का नतीजा जनतंत्र की हत्या व फासीवाद का उदय होगा.... मजदूरों के जीवन स्तर व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए सीटू यूनियनों का यह काम है कि वे लगातार मजदूरों के सामने यह बात लायें कि जब तक नीतियों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता तब तक हालात में कोई खास सुधार संभव नहीं है. मजदूर वर्ग के हित सारी जनता के हित से जुड़े हुए हैं."

विकल्प : कामरेड राममूर्ति ने बताया कि "अपने रोज के अनुभवों से सीखते हुए मजदूर वर्ग में बुनियादी परिवर्तनों के प्रति आस्था बढ़ रही है इससे हमारे सामने यह आशा बढ़ जाती हैं कि हम मजदूर वर्ग को इन नीतियों के बुनियादी परिवर्तन कराने के लिए संघर्ष के रास्ते पर बढ़ा सकें. सीटू का स्वतंत्र व उत्साही काम एकता बनाने व एकजुट संघर्ष को बढ़ाने में बहुत जरूरी रहा है...इस संघर्ष से ही वर्ग ताकतों का दुबारा वर्गीकरण होगा तथा एक सही वामपंथी व जनवादी विकल्प उभरेगा. यह विकल्प ही सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों से सही प्रकार से संघर्ष कर सकेगा, देश को तेज विकास की दिशा में ले जायेगा तथा गरीबी व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करेगा."

अंतर : सीटू के कार्यकर्त्ताओं की प्रशंसा करते हुए और दमन की चर्चा करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "पिछले और इस सम्मेलन के बीच के समय में हमारे साथियों को अभूतपूर्व जुल्म की आग में से निकलना पड़ा है--- कई प्रदेशों में हमारे साथियों को शासक वर्ग की सरकार तथा मालिकों द्वारा गैरकानूनी तरीकों से रखी गई अर्द्धफौजी सेनाओं व पालतू गुण्डों की जमातों के हमलों का सामना करना पड़ा. तमिलनाडु में अन्ना डी. एम. के. की सरकार ने सीटू को अपने हमलों का मुख्य लक्ष्य बनाया है---अन्य राज्यों में मेहनतकश जनता पर हो रहे इस जुल्म के बिलकुल विपरीत पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की सरकारों का रुख है जहां एक भी मजदूर को गिरफ्तार नहीं किया गया है और एक भी गोली मजदूरों पर नहीं चलाई गई है. पुलिस को सख्ती के साथ यह आदेश दिया गया है कि वे मजदूरों के संघर्षों में दखलंदाजी न करें.

[शेष पृष्ठ 30 पर]

मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सीटू कटिबद्ध

[पृष्ठ 29 से आगे]

शक्ति : आज सीटू मजदूर आंदोलन में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है. इसे सभी मजदूर सच्ची व निर्भर करने योग्य ऐसी संस्था के रूप में जानते हैं जो हमेशा उनके हितों की रक्षा करेगी. इसकी वजह बताते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "ऐसा होना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सीटू···अपने जन्म से ही यह मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, यह मजबूती से वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलती है तथा 'एकता व एकजुट संघर्ष के नारे पर ईमानदारी से अमल करती है. सीटू जुल्म व त्याग की आग से तप कर निकली है."

अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता : सीटू के विकास तथा हमारे देश के मजदूर आंदोलन में बनाई गई अपनी साख के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता मिलनी शुरू हो गई है.

संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का खुलासा पेश करते हुए कामरेड राममूर्ति ने कहा कि "1977 में सीटू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ. एल. ओ.) द्वारा जेनेवा में बुलाई गई रंगभेद विरोधी सम्मेलन में बुलाया गया. सीटू के महासचिव ने इस सम्मेलन में भाग लिया. इस मौके पर इंग्लैंड, फ्रांस तथा इटली भी गए और ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा फ्रांस के सी. जी. टी. व इटली के सी. जी. आइ. एल. के महासचिवों से ट्रेड यूनियन आंदोलन के अहम मुद्दों पर बात चीत की.···पिछले वर्ष वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्ज (डब्ल्यू. आफ. टी. यू.) ने, जोकि अब तक सीटू को मान्यता नहीं देते थे, हमारे एक प्रेक्षक प्रतिनिधि को प्राग (चैकोस्लोवाकिया) में हो रहे सम्मेलन में भाग लेने का न्यौता दिया... हमें डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की ट्रेड यूनियनों से लगातार निमन्त्रण मिल रहे हैं तथा हमारी संस्था के कई प्रतिनिधि इन सम्मेलनों में भाग लेते रहें हैं···अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) ने कोयले की खदानों में सुरक्षा के उपायों को देखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था. प्रतिनिधिमंडल सीटू के दफ्तर भी आया तथा हमारे महासचिव व सचिव से इस समस्या पर विस्तार से बातचीत की. यह बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण रही···ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दो पदाधिकारी सीटू दफ्तर आये व उन्होंने हमसे लम्बी बातचीत की. उन्होंने हमारी संस्था के साथ भाईचारे के संबंध बनाने की तथा प्रकाशनों के आदान-प्रदान की इच्छा जाहिर की. यह काम शुरू हो गया है."

अंत में सीटू के महासचिव कामरेड राममूर्ति ने सम्मेलन का आह्वान करते हुए कहा "आओ हम 'एकता व एकजुट संघर्ष' का झंडा और भी बुलन्द करें तथा वैकल्पिक नीतियों के लिए अपने एकजुट संघर्ष को और आगे ले जायें. हमें विश्वास है कि हम तमाम मजदूर जनता को अपने वर्ग के साथ लाने में सफल होंगे."

मजदूरों मे सीटू का असर और प्रतिष्ठा बढ़ी

[पृष्ठ 26 से आगे]

कहा कि "कुल मिलाकर सीटू के अखबार अपने सदस्यों को शिक्षित करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं. प्रतियों की बढ़ती हुई तादाद और अन्तर्वस्तु में सुधार को देखकर कहा जा सकता है कि मजदूरों के लिए उनकी उपयोगिता को और बढ़ाया जा सकेगा."

सीटू केन्द्र : बंबई कांफ्रेंस के बाद से सीटू केंद्र की गतिविधियों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, साथ ही, केंद्र ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी संभाली है. पूरे देश के स्तर पर सामूहिक आंदोलनों में तेजी आ रही है, सीटू केंद्र को इन गतिविधियों को संगठित करने व सुचारु रूप से चलाने के लिए और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. इसका जिक्र करते हुए कामरेड पंधे ने कहा कि "राज्य कमेटियों से और भी मदद की उम्मीद है जिससे कि केंद्र को ऐसे कामरेडों की सहायता मिल सके जो केंद्र की विशिष्ट जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें. सीटू सेंटर के साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं को जोड़ना भी जरूरी हो गया है जिससे वे काम जिनमें इस वक्त गलतियां हो जाती हैं, सही तरीके से किये जा सकें."

असर और प्रतिष्ठा : सभी स्तरों पर सीटू संगठनों को मजबूत बनाने के कार्य पर जोर देते हुए सीटू सचिव कामरेड पंधे ने कहा कि "सीटू का असर और प्रतिष्ठा आम मजदूरों के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गयी है. सीटू की सदस्यता करीबन 15 लाख तक बढ़ पायी है, उन मजदूरों की तुलना में जो हमारे साथ संघर्ष में उतरते हैं या हमें समर्थन देते हैं, हमारी सदस्य संख्या बहुत कम है."

"यद्यपि हमने अनेक सामूहिक संघर्षों और आंदोलनों में हिस्सेदारी की है मगर इसके बावजूद हम असरदार तरीके से अपनी स्थिति केंद्रीकृत नहीं कर पाए हैं. इसी वजह से हमारा असर बिखरा-बिखरा है. और अपने कामों में हुई बढ़ोत्तरी का संगठन की मजबूती के हक में उपयोग नहीं कर पाये हैं."

गुप्त सर्कुलर : उन्होंने कहा कि "हमारे संगठन के विरुद्ध गृह मंत्रालय द्वारा सर्कुलर जारी किए जाने की खबर से पता लगता है कि सरकारी तंत्र हमारे संगठन की प्रगति से कितना डरा हुआ है. अगर इससे हमें अपनी ताकत बारे संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए हमें अपने आंदोलन को अच्छी तरह केंद्रीभूत करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए जिसके बिना आगे बढ़ने का काम बहुत

अगुवा-दस्ता : रिपोर्ट के अंत में सार प्रस्तुत करते हुए सीटू सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने कहा कि "सीटू के और अधिक मजबूत होने की आशा काफी उज्तवल है. यह हमारी सभी यूनियनों

[शेष पृष्ठ 36 पर]

बेरोजगारी पर

सीटू का यह चौथा सम्मेलन देश में लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करता है.

हाल ही में श्रममंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक दिसंबर 1978 तक देश के 535 रोजगार दफ्तरों में दर्ज बेरोजगारों की तादाद एक करोड़ पच्चीस लाख हो गई है. 1972 के अंत तक दर्ज बेरोजगारों की तादाद 68,90,000 थी, छः सालों के दौरान बेरोजगारों की तादाद में 57 लाख की बढ़ोतरी और हो गई. इससे पता लगता है कि बेरोजगारों की औसतन बढ़ोतरी 10 लाख फी साल हुई. जून 1978 तक पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद 60,80,000 हो गई है. यह तो सभी जानते हैं कि नाम दर्ज बेरोजगारों की तादाद से देशभर के सभी बेरोजगारों की तादाद का सही पता नहीं लगता. हाल ही में योजना पत्रों के अनुसार 1977-78 में रोजगार अंतर 4,07,00,000 स्टैण्डर्ड व्यक्ति वर्ष था. दूसरे शब्दों में चार करोड़ से भी ऊपर की तादाद में लोग बेरोजगार थे.

इस संमेलन का पक्का विचार है कि इस बेरोजगारी की असली जड़ विकास का पूंजीवादी रास्ता है जिसपर पहले कांग्रेस पार्टी चलती रही और अब जनता पार्टी चल रही है. दोनों की ही जमींदारों और विदेशी तथा भारतीय इजारेदारी पूंजी से सांठ-गांठ रही है जिन पर वे निर्भर करती रही हैं. इस सम्मेलन को यह मालूम है कि मौजूदा पूंजीवादी समाज के ढांचे के भीतर रहते हुए बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती, इसलिए अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलना और समाजवाद की ओर आगे बढ़ना लाजिमी है. इसी के साथ, इस सम्मेलन का यह भी विचार है कि अगर वर्तमान योजना की दिशा को सही मोड़ दे दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या को कुछ कम जरूर किया जा सकता है.

इस सम्मेलन की यह धारणा है कि जनता सरकार की यह घोषणा जो उन्होंने केंद्र की सत्ता हाथ में आते ही की थी कि बेरोजगारी की समस्या दस साल में खत्म हो जायगी बिलकुल झूठ और धोखा है. जहां एक ओर जनता सरकार बेरोजगारों के लिए चिंतित होने का ढ़ोल पीटती है, वहां दूसरी ओर ऐसे कदम उठाने से भी बाज नहीं आती जिससे बड़े पैमाने पर छटती हो रही है और रोजगार के अवसर भी कम होते जा रहे हैं. इसके अलावा सरकार कोई ऐसे असली और असरदार कदम नहीं उठा रही है जिससे देश में रोजगार मुहैय्या हो सके.

यह सम्मेलन पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार को बेरोजगारी भत्ते की योजना को शुरू करने के लिए बधाई देता है. हांलाकि ऐसी स्कीमों से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पायगी, मगर फिर भी वामपंथी मोर्चे की सरकार ने इस सिद्धांत का परिचय जरूर दिया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह या तो रोजगार दे या बेरोजगारी भत्ता.

यह संमेलन मांग करता है कि हमारी योजना कि दिशा को ऐसा मोड़ दिया जाय जिससे : (1) इजारेदार पूंजीपतियों को, चाहे वे विदेशी हों या देशी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाय, (2) मूलगामी भूमि सुधार के कार्य पूरे हो सकें.

यह संमेलन आगे यह मांग करता है कि :

1. काम का अधिकार संविधान में मूल अधिकार के रूप में माना जाय.

2. देहाती और शहरी बेरोजगारों को काम देने या बेरोजगारी राहत देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले.

3. समूचे औद्योगिक संस्थानों में पूरी उत्पादन क्षमता काम में लाई जाय.

4. छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग धंधों को सहायता और कर्ज दिया जाय.

5. सारे बेरोजगारों का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए.

6. वरिष्ठता के आधार पर रोजगार दफ्तरों के जरिए भरती को अनिवार्य बनाया जाय.

सीटू ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह बात ध्यान में रखने की याद दिलाता है कि शासक वर्ग बेरोजगारों और निराश युवकों को हमेशा मेहनकशों के बहादुराना वर्ग-संघर्षों को तोड़ने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. ट्रेड यूनियन तथा हमारे दूसरे वर्ग संगठनों की प्रतिक्रियावादी ताकतों की इन घिनौनी चालों को नाकाम बनाने के लिए बेरोजगारों के हितों के लिए भी संघर्ष करना होगा.

यह संमेलन सभी बेरोजगारों का आह्वान करता है कि वे एकजुट हों और संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा दूसरी जनवादी ताकतों के सहयोग से अपना भी मजबूत आंदोलन शुरू करें. यह सम्मेलन खासतौर से संगठित मजदूर वर्ग से अनुरोध करता है कि समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के हित को ध्यान में रखते हुए वे बेरोजगारों के आंदोलन को संगठित करने की पहलकदमी करें.

यह संमेलन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वे बेरोजगारों के हितों के समर्थन में एकजुट होकर जेहाद शुरू करें.

दमन पर

[पृष्ठ 20 से आगे]

आह्वान करता है कि वह इन हमलों का डट कर मुकाबला करें और इन सरकारों की भूमिका का पर्दाफाश करने के लिए और अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों और ट्रेड यूनियनों के काम करने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक देश व्यापी संगठित आंदोलन चलायें.

यह सम्मेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय संघों से इस बात की अपील करता है कि वे भारतीय मजदूर वर्ग के हित में इन हमलों का संगठित होकर मुकाबला करें और सभी दमनकारी कदमों को वापस लेने तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन में पुलिस तथा मालिकों के गुंडा गिरोहों के हस्तक्षेप बन्द करने की जोरदार मांग करें.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में वेतन समझौतों पर

सीटू का यह चौथा सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में समझौतों के दौरान की जाने वाली ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज की उस दखलन्दाजी के खिलाफ अपने पुरजोर गुस्से का इजहार करता है जिसकी वजह से द्विपक्षीय वेतन-समझौतों का तंत्र ही मजाक बनकर रह गया.

दिल्ली में 15 मई 1978 **को सार्वजनिक** क्षेत्र के उद्योगों की यूनियनों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें बी. पी. ई. और भूतलिंगम कमेटी की सिफारिशों के खात्मे की पुरजोर मांग की गई थी. 28 जून 1978 को होने वाली एक दिन की हड़ताल का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन के इतिहास में अपनी किस्म की पहली मिसाल था.

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की बढ़ती हुई आक्रामकता से चौकन्ना होकर सरकार ने 26 जून 1978 को मजदूरों के नुमाइन्दों से वायदा किया कि पहले उनके साथ दिशानिर्देश की रूपरेखा पर बातचीत होगी और सरकार वेतन समझौतों में दखलन्दाजी नहीं करेगी. इन वायदों की वजह से हड़ताल वापस ले ली गयी थी. हालांकि तब से अब तक नौ महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं मगर फिर भी सरकार ने ट्रेड यूनियनों के साथ किसी अर्थवान बातचीत का सिलसिला शुरू करने की ओर गंभीरता नहीं दिखाई है. इसके विपरीत बी. पी. ई. ने मनमाने तरीके से एक सक्यूंलर सभी सार्वजनिक उद्योगों को भेज दिया है जिसमें उन्हें पहले वाले निर्देशों पर ही चलने का हुक्म दिया गया है.

बी. पी. ई. के द्वारा जारी किए गए अपमानजनक निर्देशों में कीमत सूचकांक (1960 का आधार) में फी प्वाइंट बढ़ोतरी पर महंगाई भत्ते को रु० 1.30 पर जाम कर देने, सारे वेतन समझौतों में मजदूरों की वेतन वृद्धि को दस फी सदी की सीमा पर रोक देने, मकानों के निर्माण पर रोक और छुट्टी की सुविधाओं पर रोक जैसी बातें शामिल हैं जिसकी वजह से मजदूरों की बहुत सारी मांगों को समझौतों में शामिल नहीं किया जा सकेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी को सरकारी निर्देश मिल जाने से एस. ए. आई. एल. ('सेल'), सी. आई. एल. बी. एच. ई. एल ('भेल') और अन्य कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में द्विपक्षीय वेतन समझौतों में गतिरोध पैदा हो गया है. कई बार प्रबंधकों के नुमाइंदे समझौते की मेज पर आमने सामने बैठकर मांगों को जायज मान लेते हैं मगर बी. पी. ई. के द्वारा जारी किए गए आदेशों का जिक्र करके अपनी लाचारी दिखा देते हैं.

ऐसे कई वाकयात हुए हैं जबकि मजदूरों को यूनियन से हुए समझौतों पर अमल करवाने के लिए हड़तालें करवानी पड़ी हैं जैसाकि हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स (मद्रास), हिंदुस्तान, केबिल्स (रूपनारायणपुर), वालमेर लौरी एण्ड कं० (बंबई), रिचर्डसन क्रूडर (बंबई) और हिंदुस्तान फोटो फिल्मज (ऊटी) में हुआ.

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के बीच बढ़ते हुए असंतोष का सीटू को अहसास है. सीटू की मांग है कि सरकार बी. पी. ई. द्वारा जारी किए गए निर्देशों को तुरन्त वापिस ले और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में वेतन समझौतों में दखलन्दाजी करना बंद करे. **सीटू** यह भी मांग करती है कि ऐसे सारे समझौते जो शुरू हो चुके हैं पूरे किए जायं और मजदूरों की बहुत दिनों से चली आ रही मांगें पूरी की जायं.

सीटू सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आश्वासन देती है कि अगर वे वेतन समझौतों में बी. पी. ई. की दखलंदाजी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे तो **सीटू** उनका तहेदिल से साथ देगी.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1978 दिस.	1979 जन.	फर.
बिहार			
जमशेदपुर	325	318	316
झारिया	321	314	312
कोडर्मा	343	341	340
मोंघाइर	348	338	340
नोआमुंडी	315	312	311
गुजरात			
अहमदाबाद	323	322	321
भाव नगर	341	336	334
हरियाणा			
यमुना नगर	359	357	356
जम्म व काश्मीर			
श्रीनगर	335	332	332
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	359	355	353
भोपाल	341	338	335
ग्वालियर	347	346	342
इंदौर	357	356	356
महाराष्ट्र			
बंबई	326	324	323
नागपुर	329	328	324
शोलापुर	353	347	343
पंजाब			
अमृतसर	350	351	347
राजस्थान			
अजमेर	342	343	341
जयपुर	358	357	354
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	339	336	334
सहारनपुर	347	344	342
वाराणसी	398	392	388
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	347	345	342
कलकत्ता	338	331	325
दार्जीलिंग	280	276	276
हावड़ा	328	321	317
जलपाइगुरी	275	273	273
रानीगंज	329	329	325
दिल्ली	369	368	368
भारत	335	332	329

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर

सीटू का यह चौथा सम्मेलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्धारण में लगातार होने वाली धोखाधड़ी पर गंभीर चिंता प्रकट करता है. इस धोखाधड़ी द्वारा भारतीय मजदूर वर्ग को हर महीने करोड़ों रुपयों से वंचित किया जा रहा है जिससे उनकी सही मजदूरी गिर रही है. मूल्य सूचकांक का यह गलत निर्धारण एक तरह का वेतन जाम ही है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जनता सरकार द्वारा बनाई गई पुनरावलोकन समिति मजदूर वर्ग के हितों को बचाने में असफल रही है. सूचकांक में की जा रही धोखाधड़ी के बारे में प्रमाण व तथ्य दिये जाने तथा सीटू व बी. एम. एस. द्वारा लिखित रूप में विरोध पत्र दिये जाने के वावजूद इस समिति ने बहुमत का प्रयोग कर मजदूरों के हितों की अनदेखा किया. इस विषय पर श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के विचार जानने से पहले ही लेबर ब्यूरो की सलाह के आधार पर ही फैसला कर लिया. सीटू का सम्मेलन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के इस व्यवहार का जोरदार विरोध करता है तथा मांग करता है कि लेबर ब्यूरों से इन सुझावों को मान लेने से पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा किया जाये.

मूल्य सूचकांक में धोखाधड़ी का आरंभ परिवार जीवनयापन सर्वेक्षण के गलत आधार, मूल्यों का गलत संकलन वस्तुओं की मात्रा व गुण के अनुसार उनके विभिन्न मूल्यों को समन्वित न किया जाना तथा जो वस्तुएं सरकारी दुकानों पर राशन के रूप में मिलती हैं उनके बाजार के दाम का बिल्कुल ध्यान न करना आदि से होता है. परिवार जीवनयापन सर्वेक्षण एक-सदस्यीय परिवारों तथा मजदूर वर्ग के निर्धनतम हिस्सों में से होता है. इन परिवारों के अधिकतर लोगों को सारे साल भर काम नहीं मिलता या मंहगाई भत्ता इत्यादि सुविधायें नहीं मिलती हैं. इस कारण इन परिवारों के आधार पर किया गया सर्वेक्षण सही व विश्वसनीय नहीं हो सकता. मूल्य सूचकांक निकालने के ये सब तरीके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के बताये हुए मानों के विरुद्ध है तथा बार-बार विरोध किये जाने के बावजूद भी इन्हें सुधारा नहीं गया है.

यह सम्मेलन इस बात पर भी गम्भीर चिन्ता प्रकट करता है कि इन्टक, एच० एम० एस० तथा एटक के प्रतिनिधियों ने पुनरावलोकन समिति में सीटू व बी० एम० एस० द्वारा रखें गये विरोध-पत्र का समर्थन नहीं किया. इन ट्रेड यूनियनों द्वारा ऐसा रुख अपनाने से उपभोक्ता दूल्य सूचकांक में यह धोखाधड़ी चलती रहेगी तथा मालिक वर्ग इस प्रनार हर महीने मजदूरों को करोड़ों रुपयों के लाभ से वंचित करता रहेगा पुनरावलोकन समिति की बहुमत बाली रिपोर्ट ने 1971 श्रेणी को लागू करने की सिफारिश की है जिससे मजदूरों को आमदनी में भारी कमी होगी 1971 की श्रेणी गलत है तथा इस पर निर्भर नहीं किया जा सकता. इससे अतिरिक्त जब तक 1960 की श्रेणी की गलतियों व धोखाधड़ी को ठीक नहीं किया जाता तब तक यह गलतियां व धोखाधड़ी 1671 की श्रेणी में गलत परिवर्तन के तरीके से आ जायेंगी. इसलिए मजदूर वर्ग के हितों को मद्धेनजर रखते हुए 1971 की श्रेणी को लागू नहीं होने दिया जाना चाहिये.

सीटू का यह चौथा संमेलन सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वे एकजुट हो तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निधारण में होने वाली धोखाधड़ी को खत्म कराने के लिए एकजुट आंदोलन शुरु करें, वे यह भी मांग करें कि पुनरावलोकन समिति के सुझावों को रद्द किया जाये तथा 1971 श्रणी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तब तक लागू न किना जाये जब तक 1960 श्रेणी की गलतियों को ठीक न किया जाये व 1960 और 1971 श्रेणी के बीच परिवर्तन प्रणाली को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की इच्छानुसार न बनाया जाये.

जनरल काउंसिल के सदस्य

[पृष्ठ 22 से आगे]

पी. उन्नी, वी. कृष्णदास, पी. कुन्हीकन्नन, पी. के. कृष्णन, वी. जी. भास्करन नायर, टी. एम. मुहम्मद, सी. के. वसु, के. आर. गंगाधरन, पी. रत्नामल‡, के. एम. अब्राहम, वी. आर. रमन कुट्टी, थोप्पिल धर्मराजन, पेरुरकदा सदाशिवन, के. अनीरुधन, आर. परमेश्वरन नायर, के. एन. शाहुल हमीद, जोसेफ चावेली, सारदा राजन‡, वी.बी. चेरियन, के. थुलासिधरन, एम. सुन्दरेश्वरम, ई. कासिम, सी. इंदिरा‡, पीं. केसावन नायर, एम. जी. धनापल, के थंकाप्पन, एन. बी. त्रिवीक्रमन पिल्लै, के. पी. एस. मेनन. और का. एम. के. विश्वमभरन.

आंध्र प्रदेश

कामरेड एन. प्रसाद राव*, पी. सुन्दारैय्या*, पी. सत्यनारायण*, एन. वी. भास्कर राव, जी. एस. बालाजी दास, पी. लक्ष्मीदास, वी. श्रीहरी और का. मनीश्याम‡.

पंजाब

कामरेड जगजीत सिंह लायलपुरी, बलवन्त सिंह और का. मंगत राम.

गुजरात

कामरेड बी. वी. मैंहदले और का: हरीकृष्ण शाह.

सी. आई. टी. यू. केन्द्र

कामरेड विमल रणदिवे और चार स्थान बाद में भरे जाएंगे.

नोट : * वर्किंग कमेटी के सदस्य.
‡ महिला सदस्य.

अंग्रेजी में
सीटू का मासिक मुखपत्र
'दि वर्किंग क्लास'

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
वार्षिक चंदा 6 रुपये
एजेंसी के लिए कम से कम 5 प्रतियां
लिखें : मैनेजर,
दि वर्किंग क्लास
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की बाबत

सीटू का यह चौथा संमेलन इस बात पर गंभीर चिंता प्रकट करती है कि जबसे केन्द्र और राज्यों में जनता सरकारें बनी हैं तबसे हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार घटने के बजाय बढ़ रहे हैं. हरिजनों पर अत्याचार अमली तौर पर लगभग पूरे देश में अबाध गति से हो रहे हैं हालांकि कुछ राज्य जैसे बिहार काली सूची में सबसे ऊपर हैं. अभी हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने लोक सभा में दिए अपने एक बयान में बताया कि 1978 के वर्ष के दौरान हरिजनों के 412 कत्ल और 478 बलात्कार हुए. बेलची, बाचीतपुर, कैला और मराठवाडा रोजमर्रा की घटनाएं बन गए हैं.

सीटू का यह संमेलन महसूस करता है कि ये मसले सिर्फ मानवतावाद के मसले ही नहीं हैं बल्कि इनका एक आयाम आर्थिक और वर्गीय है. जो लोग इन अत्याचारों को कर रहे हैं वें न सिर्फ ऊंची जातियों के हैं बल्कि शोषक वर्गों के भी हैं. दूसरी ओर उत्पीड़ित लोग तथा कथित हरिजन या आदिवासी तो है ही साथ ही देहात के गरीब वर्ग के लोग हैं. हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों का गहरा संबंध देहातों में बढ़ते हुए वर्ग-संघर्षों से है जिनका केन्द्र है जमीन का मसला. ऊंची जातियों के लोग क्रोध में पागल हो उठे हैं और मेहनतकशों की इस जमीन को पाने के लिए नित बढ़ती जा रही वर्ग-लड़ाई को दबाने पर आमादा हो उठे हैं जिसे वे अपने खून से सींच कर जोतते बोते हैं.

इस संमेलन का यह निश्चित विचार है कि गांवों में ऊंची-जातियों से संबंधित शोषकों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन को एक सामूहिक मंच के तहत एकजुट होने की दिशा में बढ़ाना होगा तथा उसे जातिप्रथा के खिलाफ लड़े जाने वाले व्यापक जनवादी और मानवतावादी आंदोलन से जोड़ना होगा. इस आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक वर्ग-संघर्षों के माध्यम से हरिजनों और आदिवासियों में साहस पैदा करना तथा हिंसा के खिलाफ प्रतिरोधी ताकत को एकजुट करना होगा. यह सम्मेलन महसूस करता है कि जनता सरकार ने इस समस्या को हल करने और हरिजनों व आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने के सिलसिले में पूरा दिवालियापन दिखाया है. सचाई यह है कि जनता सरकार के बड़े हिस्सेदार चूंकि कुलकों के नुमाइंदे हैं अतः गांवों के गरीब हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले इन अत्याचारों में वे शामिल हैं. यह सम्मेलन मांग करता है कि जनता सरकार अपने उन वायदों को पूरा करने में अब देर न लगाए जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे और हरिजनों व आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करने के लिए असरदार कदम उठाए. यह सम्मेलन यह भी मांग करता है कि इससे संबंधित सरकारें (1) सचमुच बड़े पैमाने पर असरदार तरीके से भूमि का फिर से बंटवारा करें जिससे कि देहातों के गरीब लोगों को जमीन मिल सके. (2) अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएं और उन्हें कडी सजा दें (3) और निर्मम हो कर भ्रष्ट जातिवादी अफसरों को बिना किसी रियायत के निकाल बाहर करें.

यह संमेलन मजदूर वर्ग और जनवादी ताकतों से अपील करता है कि हरिजनों और आदिवासियों पर ढाए जा रहे जुल्मों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलन्द करें. यह सम्मेलन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि ऊपर बतायी गयी मांगों के समर्थन में एक मजबूत जेहाद शुरु करें जिससे कि जनता सरकार को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर होना पड़े.

चौथे सम्मेलन में चुने गए
सीटू के पदाधिकारी

अध्यक्ष :
का० बी. टी. रणदिवे

उपाध्यक्ष :
का० ज्योति बसु
का० मुहम्मद इस्माइल
का० सुहृद मलिक चौधरी
का० सुधीन कुमार
का० एस. वाई. कोल्हाटकर
का० सुशीला गोपालन
का० सी. कन्नन
का० के. रमानी
का० मनोरंजन राय

जनरल सेक्रेटरी :
का० पी. राममूर्ति

सेक्रेटरी :
का० एम. के. पंधे
का० ई. बालानंदन
का० कमल सरकार
का० नीरेन घोष
का० मोहन पुनमिया
का० नृसिंह चक्रवर्ती
का० एस. एस. बोस

कोषाध्यक्ष :
का० समर मुखर्जी

इस्पात मजदूरों के नाम सीटू अध्यक्ष की अपील

फौरी मांगों को हासिल करने के लिए 18 मई को हड़ताल तथा दूसरी कार्यवाहियों की मदद से "इस्पात मजदूर मांग दिवस" के रूप में मनाएं.

30 अप्रैल, 1979

प्रिय साथियो,

9 महीने से ज्यादा अरसे से इस्पात-मंत्रालय की राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति में द्विपक्षीय बातचीत चल रही है लेकिन इस्पात कारखानों के प्रबंधक बातचीत को लंबा खींचने के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं. इससे समझौते में रुकावट आती है. बैठक पर बैठक हो रही हैं लेकिन मामला जहां का तहां है.

इस्पात-मंत्रालय तथा सार्वजनिक उद्यमों का ब्यूरो परदे के पीछे से द्विपक्षीय बातचीत में दखलअंदाजी कर रहे हैं और फैसला न होने देने की जिम्मेदारी इन दोनों पर भी है.

न्यूनतम वेतन, जीवन-स्तर मंहगा हो जाने की सौ फीसदी भरपाई, छुट्टी की सुविधाएं, बढ़ावा देने की योजना में सुधार, समान वेतनमान, ठेके पर मजदूरी के रिवाज का खात्मा आदि प्रमुख सवालों पर बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. इन मांगों को पूरा न करके, छोटी-मोटी मांगों पर थोड़ी-बहुत रियायत देने से मजदूरों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता.

इस्पात-मजदूर अनेक प्रदर्शनों और विरोध कार्यवाहियों द्वारा इस रवैये के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं. सीटू द्विपक्षीय बातचीत के आरंभ से ही मजदूरों को बताती आयी है कि जब तक अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष नहीं होता तब तक इस्पात-प्रबंधक मजदूरों की मांगों को मानने पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे.

सीटू ने प्रबंधकों के रवैये के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए सभी ट्रेड-यूनियनों का बार-बार आह्वान किया है. लेकिन कुछ लीडरान संघर्ष के लिए तैयार नहीं. वे मेज पर बैठकर सिर्फ बातचीत के जरिए कुछ मामूली रियायत हासिल करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं. प्रबंधक मजदूरों के इस हिस्से की कमजोरी को पहचानते हैं और मजदूरों में फूट डालने की कोशिश में वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते.

कोयला-उद्योग में सभी केंद्रीय ट्रेड-यूनियनें एकजुट हो चुकी हैं और संघर्ष की राह पर चल पड़ी हैं. उन्होंने 5 फरवरी को एक दिन की हड़ताल की और अब 18 मई, 1979 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियों में जुटी हैं.

सीटू की ओर से मैं 2 लाख 40 हजार इस्पात-मजदूरों का आह्वान करता हूं कि वे 18 मई को इस्पात-मजदूर मांग-दिवस के रूप में तमाम हिंदुस्तान के पैमाने पर मनाएं. मैं सभी केंद्रीय ट्रेड-यूनियनों और स्वतंत्र यूनियनों से अपील करता हूं कि इस्पात-मजदूरों की मांगों पर जोर देने के लिए वे सभी इस कार्यवाही में शरीक हों.

इस दिन मजदूरों को हड़ताल, जन-प्रदर्शन और धरने आदि सभी संभव एकजुट कार्यवाहियों का आयोजन करना चाहिए, ताकि मजदूरों की देर से चली आ रही इन मांगों को मंजूर करने पर प्रबंधकों को मजबूर होना पड़े.

मुझे विश्वास है कि इस्पात-मजदूर अपनी जुझारू परंपरा को कायम रखते हुए 18 मई, 1979 के दिन हड़ताल तथा दूसरी सीधी कार्यवाहियों में एकजुट होकर भाग लेंगे.

मैं उम्मीद करता हूं कि इस्पात प्रबंधक हालात की गंभीरता को समझेंगे और इस्पात-मजदूरों की बहुत दिनों से चली आ रही मांगों का निपटारा करने के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर सामने आयेंगे.

इस्पात मजदूरों का एकजुट आंदोलन जिंदाबाद!

बी. टी. रणदिवे,
अध्यक्ष, सीटू

मई दिवस घोषणा-पत्र

[पृष्ठ 2 से आगे]

या बेरोजगारी भत्ते आदि. संविधान में रोजगार के अधिकार को शामिल करना.

3. औद्योगिक संबंध बिल और अस्पताल व शिक्षा संस्था बिल को वापस लेना और रद्द करना. सभी दमनकारी व्यवस्थाओं की वापसी और ट्रेड यूनियनों तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद करना.

4. सभी को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देना और वेतन जाम की सभी व्यवस्थाओं को वापस लेना. महंगाई भत्ते की सौ फीसदी भरपाई करना और उपभोक्ता मूल्य निर्धारण करने वाले सूचकांक में जालसाजी करने पर रोक लगाना.

5. मूलगामी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन. सभी तरह के सामंती शोषण का खात्मा. भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों को पर्याप्त राहत और किसान उत्पादकों को उनकी पैदावार के उचित दाम

6. मिलबंदी, तालाबंदी, ले आफ और छंटनी पर पाबंदी. सभी बंद फैक्टरियों, मिलों, चाय बागान, खानों और संस्थानों को दुबारा से खोलना.

7. सभी को बोनस देना और ट्रेड यूनियनों द्वारा की गयी मांगों के अनुरूप बोनस भुगतान एक्ट में संशोधन.

8. सभी क्षेत्रों में कामगार महिलाओं के साथ बराबरी और उनके अधिकारों की रक्षा.

9. टैक्स भार में कमी और जरूरी चीजों को राशन की दरों पर मुहैया करना.

इन फौरी मांगों के गिर्द हमारी एक लगातार बढ़ती हुई एकता एक ऐसा शक्तिशाली स्तंभ बन जायगी जिस पर वाम और जनवादी ताकतों की दीवार उठायी जा सकेगी और उसकी जबर्दस्त ताकत से तानाशाही की ताकतों को पराजित करना और मालिकान, इजारेदारों तथा बड़े जमींदारों की ताकत को रोकना और उनकी जनविरोधी नीतियों को पराजित करना संभव होगा.

No. D(C)-833

कोयला मजदूरों की 18 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल

सीटू, एटक, एच. एम. एस. और इंटक ने 20 अप्रैल को जारी की गई एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कोयला प्रबंधक छः लाख कोयला खदान मजदूरों की न्यूनतम मांगों को पूरा करने के लिए नए प्रस्ताव पेश करने में नाकामयाब हुए हैं.

कोथला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी में इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कोयला खदान मजदूरों की जायज मांगों को प्रति कोयला प्रबंधकों और सरकार के इस मजदूर विरोधी रवैये की कड़ी निंदा की है. इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस रवैये के कारण अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है. इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लंबे अरसे से चली आ रही अपनी जायज मांगो पर जोर देने के लिए कोयला खदान मजदूरों का 18 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आह्वान किया है.

भारत के समूचे मजदूर वर्ग से कोयला खदान मजदूरों की मांगों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए अपील की गई.

गतिविधियों की रिपोर्ट

[पृष्ठ 30 से आगे]

और कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से ही संभव होगा. तभी हम अपने संगठन को बेहतर बना सकेंगे और सभी दिशाओं में उसे फैला सकेंगे."

"आइए, हम सब साथी मिलकर कोशिश करें जिससे कि हम अपने इस संगठन को और अधिक शक्तिशाली और सुगठित बना सकें. मजदूर वर्ग हमें मजदूर-हितों का सबसे अधिक विश्वासपात्र अगुवा दस्ता मानकर हमारी ओर देख रहा है. आइए, हम उसके विश्वास को सही साबित करने की जी-जान से कोशिश करें जिससे कि आगे आने वाले दिनों में सीटू एक शानदार भूमिका अदा कर सके."

मौरीशियन वर्कर्स यूनियन, पोर्ट लुइस

कृपया आप अपने क्रांतिकारी सम्मेलन को हमारा हार्दिक सलाम और मौरीशियन मजदूरों की एकजुटता का पैगाम दीजिए.

जनरल कांफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस, रोमानिया

शिष्ट मंडल : कामरेड स्तान जार्जी (नेता), सदस्य, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जी.आर.टी.यू.सी. और कामरेड हेंटर गावरिला, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, जी.आर.टी.यू.सी.

मद्रास में सीटू के चौथे सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिष्ट मंडल ने कहा कि "सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के चौथे सम्मेलन को ट्रेड यूनियन कांफडरेशन की सेंट्रल काउंसिल और सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ रोमानिया की श्रमिक जनता की ओर से मित्रता और एकजुटता का हार्दिक संदेश देते हुए हमें बहुत खुशी है. हम सीटू के नेतृत्व को आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन के इस महत्वपूर्ण उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए, जिसने हमें भारतीय जनता के जीवन और कार्य के कुछ पहलुओं को जानने का और आपके देश की सुंदरता को देखने का अवसर दिया, बधाई देना चाहेंगे."

दोनों देशों के संबंधों, मित्रता और कई क्षेत्रों में सहयोग के विकासों का जिक्र करते हुए शिष्ट मंडल ने कहा कि "इस सम्मेलन की कार्यवाही जिसमें भारतीय मजदूरों और ट्रेड यूनियनों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, अपनी महत्वपूर्ण मांगों की रक्षा और उनको मनवाने के विए सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियस की गतिविधियों, सीटू का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष और भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुट कार्यवाहियों को मजबूत करने में सहयोग व उपलब्धियों में हमारे शिष्टमंडल की गहरी दिलचस्पी है."

रोमानिया की जनता की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "रोमानिया अब औद्योगिक-कृषिक देश है जिसमें अब औद्योगिक उत्पादन 1938 की तुलना में 42 गुना है. इसी के आधार पर हमारी जनता के भौतिक व प्रायोगिक स्तर ऊंचे हुए है और सामाजिक ढांचा बदला है."

शिष्ट मंडल ने भारतीय श्रमिक जनता के प्रति सहानुभूति और एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि "जी. आर. टी. यू. सी. दोनों देशों की श्रमिक जनता के हितों के लिए सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के साथ और भी घनी मित्रता के संबंध स्थापित करना चाहती हैं." उन्होंने सम्मेलन की सफलता की कामना की.

वियतनाम, चीन, ब्रिटेन और देश-विदेश की अन्य यूनियनों के बिरादराना संदेश अगले अंक में

संपादक मंडल
बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति — मनोरंजन राय
निरेन घोष — सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज़ केलिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1, लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन 384071)